Website : www.mantrabharat.com

जुनून है सच लिखने का

E-Mail : mantrabharatmumbai@gmail.com, Mo. 7007837917

संस्करण : मुंबई
वर्ष : 11
अंक : 27
पृष्ठ : 8
मूल्य : 2.00
मंगलवार, 03 फरवरी, 2026

मंत्र भारत

हिन्दी दैनिक

मुंबई, लखनऊ, प्रयागराज एवं ग्वालियर से एक साथ प्रकाशित एवं ठाणे, नवी मुम्बई, पालघर, नासिक एवं पुणे से प्रसारित

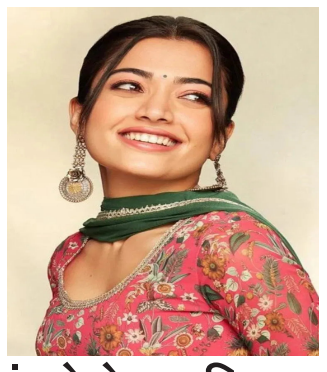

3 महाराष्ट्र की सियासत में नया अध्याय,...

4 भारत-यूरोपीय संघ समझौता- यूरोप की नई...

7 टी20 विश्व कप में भारत से खेलने से ...

संक्षिप्त न्यूज

इंडिगो फ्लाइट में बम की चिट्ठी से मचा हड़कंप, वाराणसी में हुई आपातकालीन लैंडिंग

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। हैदराबाद से वाराणसी जा रही इंडिगो एयरलाइंस की एक फ्लाइट को रविवार को बम की धमकी मिलने के बाद आपातकालीन लैंडिंग के लिए डायवर्ट किया गया। विमान में बम होने का दावा करने वाला एक हस्तलिखित नोट मिलने के बाद अलर्ट जारी किया गया। सूचना मिलते ही अधिकारियों को तुरंत सूचित किया गया और आपातकालीन प्रक्रियाएं शुरू की गईं। 200 से अधिक यात्रियों को ले जा रहा विमान बाबतपुर के लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतर गया। पुलिस ने बताया कि विमान में सवार सभी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियात के तौर पर यह निर्णय लिया गया।

लैंडिंग के तुरंत बाद सुरक्षा एजेंसियां हवाई अड्डे पर पहुंच गईं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), बम निरोधक दस्ते, अग्निशमन दल और स्थानीय पुलिस की टीमों ने विमान की विस्तृत जांच की और मानक सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सभी यात्रियों की जांच की। हालांकि, जांच के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। हवाई अड्डे के अधिकारियों ने पुष्टि की कि खतरे के स्रोत और विश्वसनीयता का पता लगाने के लिए जांच जारी है। दिल्ली-बागडोगरा इंडिगो की उड़ान ने लखनऊ में आपातकालीन लैंडिंग की

जनवरी में, बम की धमकी मिलने के बाद इंडिगो की दिल्ली-बागडोगरा उड़ान ने लखनऊ हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग की। अधिकारियों के अनुसार, सभी यात्रियों और चालक दल को सुरक्षित निकाल लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि इंडिगो की उड़ान 6ई-6650 से संबंधित बम की धमकी की सूचना सुबह लगभग 8:46 बजे वायु यातायात नियंत्रण (एटीसी) को दी गई।

दिल्ली हाईकोर्ट ने महिपालपुर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने की याचिका ठुकराई

कहा– यह डीएमआरसी और सरकार का अधिकार

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार, 2 फरवरी 2026, को मेट्रो स्टेशन के नाम बदलने से जुड़ी एक अहम याचिका पर बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने महिपालपुर मेट्रो स्टेशन का नाम 'रंगपुरी' करने की मांग को पूरी तरह खारिज कर दिया। अदालत ने साफ कहा कि मेट्रो स्टेशनों का नाम तय करना सरकार और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) का नीतिगत और प्रशासनिक अधिकार है, जिसमें न्यायपालिका तब तक दखल नहीं दे सकती, जब तक फैसला पूरी तरह मनमाना या संविधान के खिलाफ न हो।

जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की बेंच ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि अदालत न तो डीएमआरसी और न ही सरकार को स्टेशन का नाम बदलने का कोई सीधा आदेश दे सकती है। नामकरण से जुड़े फैसले पॉलिसी मैटर होते हैं और अदालत का हस्तक्षेप सीमित दायरे में ही संभव है।

हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं की शिकायत को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी

आधार पर डीएमआरसी और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे याचिका पर छह सप्ताह के भीतर गंभीरता से विचार करें और जरूरत पड़ने पर अन्य विभागों से भी राय लें। यह याचिका रंगपुरी गांव की रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) की ओर से दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं का दावा था कि– दिल्ली मेट्रो फेज-4 की गोल्डन लाइन (एयरोसिटी से तुगलकाबाद) पर बनने वाला महिपालपुर मेट्रो स्टेशन जिस जमीन पर विकसित हो रहा है, उसका बड़ा हिस्सा रंगपुरी गांव से संबंधित है। सरकार की नामकरण नीति के अनुसार स्टेशन का नाम उसी क्षेत्र के नाम पर होना चाहिए। आरडब्ल्यूए ने यह भी आरोप लगाया कि जब उन्होंने इस मुद्दे को लेकर अधिकारियों से संपर्क किया, तो उन्हें टालमटोल भरे जवाब मिले और जिम्मेदारी एक विभाग से दूसरे विभाग पर डाल दी गई।

महिपालपुर और रंगपुरी, दोनों ही इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास स्थित शहरी गांव हैं। बीते वर्षों में यहां तेजी से विकास हुआ है, लेकिन इसके साथ ही स्थानीय पहचान और नामकरण को लेकर असंतोष भी बढ़ा है। यही वजह है कि मेट्रो स्टेशन के नाम को लेकर यह विवाद सामने आया।

कोर्ट के फैसले के बाद अब सारा ध्यान डीएमआरसी और सरकार के अगले कदम पर है। सवाल यही है कि क्या वे याचिकाकर्ताओं की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे या मौजूदा नाम के साथ ही आगे बढ़ेंगे।

यह फैसला उन लोगों के लिए झटका माना जा रहा है, जो मेट्रो स्टेशनों के नामों में स्थानीय पहचान को प्राथमिकता देने की मांग कर रहे थे। दिल्ली मेट्रो फेज-4 के कई स्टेशनों को लेकर पहले भी ऐसे विवाद सामने आ चुके हैं।

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

'लद्दाख में नेपाल-बांग्लादेश जैसे हालात चाहते थे वांगचुक'

नई दिल्ली। केंद्र सरकार और लद्दाख प्रशासन ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सोनम वांगचुक लद्दाख में नेपाल और बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा करना चाहते थे। उन्होंने बताया कि वांगचुक के बयानों से हिंसा भड़कने का खतरा था। सरकार ने आरोप लगाया, 'वांगचुक ने केंद्र सरकार को 'वे' कहकर संबोधित किया, जो अलगाववादी मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने जेन जी को गृहयुद्ध और खूनखराबे के लिए उकसाने की कोशिश की।'

न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति पी.बी. वराले की पीठ के सामने सोनम वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रैं) के तहत हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका का विरोध करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह दलील दी। यह याचिका वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे. अंगमो ने दायर की है।

सॉलिसिटर जनरल ने कहा, 'वह केंद्र सरकार को 'वे' कहते हैं। यह 'हम' और 'वे' ही एनएसए के तहत हिरासत के लिए पर्याप्त है। इस देश में 'हम' और 'वे' नहीं हैं, हम सभी भारतीय हैं।' मेहता ने आरोप लगाया कि वांगचुक लद्दाख को नेपाल या बांग्लादेश जैसी स्थिति में ले जाना चाहते थे और उन्होंने युवाओं को भड़काने के लिए अपने भाषणों में महात्मा गांधी का नाम केवल एक आवरण के रूप में इस्तेमाल किया।

उन्होंने कहा कि कई बार भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं, जिनकी शुरुआत और अंत गांधीजी के नाम से किया जाता है, लेकिन बीच में हिंसा भड़काने वाली बातें होती हैं। मेहता ने वांगचुक के भाषणों का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने नेपाल और अरब क्रांति का उल्लेख करते हुए आत्मदाह जैसी घटनाओं की बात की, जिससे युवाओं को हिंसा की ओर उकसाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि वांगचुक ने आत्मदाह की धमकी देकर लद्दाख आंदोलन को अंतरराष्ट्रीय रंग देने की कोशिश की।

सॉलिसिटर जनरल ने यह भी कहा कि लद्दाख सीमावर्ती क्षेत्र है और सशस्त्र बलों की आपूर्ति श्रृंखला के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

भारत के पांच दिवसीय राजकीय दौरे पर आएंगे सेशेल्स के राष्ट्रपति, विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी

नई दिल्ली। सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी पांच से दस फरवरी तक भारत का राजकीय दौरा करेंगे। हर्मिनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर यात्रा कर रहे हैं। पिछले अक्तूबर में राष्ट्रपति का पदभार संभालने के बाद उनका यह पहला भारत दौरा होगा। विदेश मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी।

मंत्रालय ने बताया कि यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है, जब दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है।

अपने भारत दौरे के दौरान राष्ट्रपति हर्मिनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में ऐसे द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिनमें दोनों देशों की समान रुचि होगी। राष्ट्रपति हर्मिनी चेन्नई और मुंबई भी जाएंगे, जहां वह व्यापारिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे।

अरुणाचल प्रदेश की बेटी ने रचा इतिहास, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी पर फहराया तिरंगा

ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की पर्वतारोही कबाक यानो ने अपने साहस और दृढ़ संकल्प से इतिहास रचते हुए दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ (अर्जेंटीना) पर 1 फरवरी 2026 को सफलतापूर्वक चढ़ाई की। 22,831 फीट ऊंचा यह पर्वत पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी होने के साथ-साथ अनुभवी पर्वतारोहियों के लिए भी चुनौतीपूर्ण माना जाता है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल के.टी. परनाइक (सेवानिवृत्त) ने कबाक यानो को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह सफलता व्यक्तिगत विजय के साथ-साथ अरुणाचल प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है और यह दिखाती है कि अनुशासन, आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास से कठिन से कठिन लक्ष्य भी हासिल किए जा सकते हैं।

7-सम्मिट अभियान की महत्वपूर्ण उपलब्धि

कबाक यानो का यह अभियान '7-सम्मिट माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन' का हिस्सा है, जिसमें विश्व के सात महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटियों पर चढ़ाई शामिल है। इससे पहले उन्होंने 4 अगस्त 2025 को अफ्रीका की माउंट किलिमंजारो और 16 अगस्त 2025 को यूरोप की माउंट एल्ब्रुस पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी। राज्यपाल ने कहा कि कबाक यानो की यह उपलब्धि अरुणाचल प्रदेश के युवाओं में खेल, साहसिक गतिविधियों और पर्वतारोहण के प्रति नई प्रेरणा पैदा करेगी। उन्होंने युवाओं में खेल और एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन की प्रतिबद्धता भी दोहराई।

गौरतलब है कि 28 जुलाई 2025 को राज्यपाल ने इटानगर स्थित लोक भवन से कबाक यानो के '7-सम्मिट माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन' को औपचारिक रूप से रवाना किया था। कार्यक्रम में खेल एवं युवा मामलों के राज्य मंत्री केंटो जिनी भी उपस्थित थे। '7-सम्मिट माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन' में एशिया की माउंट एवरेस्ट, दक्षिण अमेरिका की एकांकागुआ, उत्तरी अमेरिका की डेनाली, अफ्रीका की किलिमंजारो, यूरोप की एल्ब्रुस, अंटार्कटिका की विंसन मैसिफ और ओशिनिया की पनचक जया या माउंट कोसियस्ज़को पर चढ़ाई करना शामिल है। यह दुर्लभ उपलब्धि अब तक केवल चुनिंदा पर्वतारोहियों ने ही हासिल की है।

मुंबई झुग्गी पुनर्वास विवादः राज्य सरकार-श्ण्उश को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, हाईकोर्ट के आदेश को बताया चुनौतीपूर्ण

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार, मुंबई नगर निगम और झुग्गी पुनर्वास प्राधिकरण सहित अन्य पक्षकारों से बॉम्बे हाईकोर्ट के विवादास्पद आदेश के खिलाफ याचिका पर जवाब मांगा। यह याचिका उन प्लॉट्स पर पुनर्वास योजनाओं को चुनौती देती है, जो मूल रूप से पार्क, उद्यान और खेल मैदान के लिए आरक्षित थे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 19 जून 2025 को डीसीपीआर 2034 के रेगुलेशन17(3)(डी)(2) को वैध ठहराते हुए कहा था कि यह नियम उपनगरीय झुग्गी पुनर्वास योजनाओं को लागू करने की अनुमति देता है, बशर्ते जनता के लिए एक हिस्से को पुनः हरित क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह संतुलन मुंबई की हरित आवरण आवश्यकता और आवास के संवैधानिक अधिकार के बीच है।

हाईकोर्ट ने जारी किए थे 17-सूत्रीय सख्त दिशानिर्देश

सुप्रीम कोर्ट की बेंच चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमल्या बागची ने वरिष्ठ वकील श्याम दिवान के तर्कों

को नोट किया। दिवान उन लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे जिन्होंने हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल की थी। उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुंबई में खुले सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा जरूरी है। हाईकोर्ट की बेंच ने हालांकि नियम की वैधता को स्वीकार करते हुए 17-सूत्रीय सख्त दिशानिर्देश जारी किए ताकि वादित खुली जगहें केवल कागज पर न रहकर वास्तविक, सार्वजनिक रूप से सुलभ सुविधाएं बनें।

पीआईएल में उठाया गया 'पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन' का मुद्दा

पीआईएल में दावा किया गया था कि आरक्षित खुली जगहों के 65 प्रतिशत पर निर्माण की अनुमति देना अतिक्रमण को वैध बनाना है और यह 'पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन' का उल्लंघन करता है। हाईकोर्ट ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि यह एक संवैधानिक संतुलन है क्योंकि ये प्लॉट वर्तमान में झुग्गियों से पूरी तरह भरे हैं और सामान्य जनता के लिए उपयोगी नहीं हैं।

हाईकोर्ट ने कहा था कि 65:35 के व्यावहारिक संतुलन, जिसमें 35 प्रतिशत भूमि जनता के लिए हरित क्षेत्र के रूप में सुरक्षित रहती है और 65 प्रतिशत भूमि झुग्गी निवासियों के लिए इस्तेमाल होती है, सटीक और अनुपातिक समाधान है। इसके तहत भूमि का विकास जॉगिंग ट्रैक, लैंडस्केपिंग और खेल उपकरण के साथ होना चाहिए और इसे केवल पुनर्वास भवन के निवासियों तक सीमित नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि भविष्य में आरक्षित भूमि पर कोई नया अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। इस मामले की लंबी कानूनी लड़ाई 2002 में शुरू हुई थी, जब 1992 की नीति को चुनौती दी गई थी, जो आरक्षित साइटों पर पुनर्विकास की अनुमति देती थी यदि वे 25 प्रतिशत तक अतिक्रमित हों।

किरेन रिजिजू का राहुल गांधी पर तीखा हमला, 'वे खुद को संसद से ऊपर समझते हैं'

नई दिल्ली। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार को विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान संसदीय नियमों का कथित उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए कहा कि लोकसभा अध्यक्ष के बार-बार निर्देश देने के बावजूद, कांग्रेस नेता अध्यक्ष को चुनौती देते रहे और विषय से भटकते रहे, जिसमें चीन सीमा का मुद्दा उठाना भी शामिल था। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया। हम सभी विपक्ष के नेता राहुल गांधी का भाषण सुनने के लिए बैठे थे। लेकिन शुरू से ही राहुल गांधी ने नियमों का उल्लंघन किया और एक ऐसी किताब का हवाला देना शुरू कर दिया, जिसके प्रकाशन और प्रामाणिकता का स्पष्ट उल्लेख नहीं है।

रिजिजू ने दावा किया कि रक्षा मंत्री और हम सभी ने कहा कि सदन नियमों के अनुसार चलेगा और नियमों के अनुसार ही बोलना चाहिए... कोई अध्यक्ष को चुनौती नहीं दे सकता।

लोकसभा अध्यक्ष के निर्देश के बाद भी राहुल गांधी वही गलती दोहराते रहे... उन्होंने आधा घंटा बर्बाद किया, नियमों का उल्लंघन किया और वही बात दोहराते रहे। उन्होंने चीन सीमा पर बोलना शुरू कर दिया... क्या कांग्रेस पार्टी 1959 और 1962 में चीन द्वारा कब्जा की गई भूमि को वापस ला सकती है?

रिजिजू ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की और उन पर संसद से ऊपर खुद को रखने और बार-बार उसके नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। रिजिजू ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जो प्रक्रिया का पालन करता है, और आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं ने व्यवधान को बढ़ावा दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि राहुल गांधी को चीन सीमा मुद्दे से संबंधित पार्टी के 'पापों' के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए।

उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। अगर कोई प्रतिष्ठित परिवार में पैदा हुआ है, तो क्या वह संसद से ऊपर है? क्या वह नियमों से ऊपर है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है।

बागेश्वर बाबा ने फिर गिनाई सनातन की कमियां बोले- जो सच है हम बोलने से चूकते नहीं

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। छतरपुर में स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीरेश्वर पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर हिंदुओं को नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म में बहुत कमियां हैं और इनमें सुधार की जरूरत है। बागेश्वर बाबा ने कहा कि दूसरों की निंदा करने की बजाय सनातनीय हिंदू खुद के आत्म सुधार पर काम करेंगे तो हमारी सनातन परंपरा अमिट रहेगी। इसको कोई मिटा नहीं सकता है। अभी सनातन को बहुत सुधार की जरूरत है। बागेश्वर बाबा ने कहा कि एक दूसरे से लड़कर साधु जो निंदा कर रहे हैं। ये सनातन के लिए घातक हैं। पुरानी कुरीतियां, रूढ़िवादिता, बलि प्रथा ये सनातन की सबसे बड़ी कमी है। उन्होंने कहा कि तीसरी सबसे बड़ी कमी जो है वह यह कि नए मंदिर तो बनाए जा रहे हैं लेकिन पुराने मंदिरों का जीर्णोंधार बंद हो गया है। चौथी कमी है हमारे मंदिर, तीर्थ देवालय केवल पिकनिक स्पॉट बन रहे हैं, आस्था के केंद्र नहीं बन रहे हैं। वहीं सबसे बड़ी कमी यह है कि हम सब एक दूसरे के सामने ज्ञान देते हैं, लेकिन एक दूसरे को साथ लेकर विश्व को ज्ञान देने की सोच नहीं रखते।

बागेश्वर बाबा ने स्पष्ट कहा कि हम सुधार की बात करते हैं, हम किसी

भी मजहब के पक्ष या विपक्ष में नहीं हैं। हम हमेशा से सनातन के पक्ष में थे, हैं और रहेंगे। लेकिन हां जो सच है वो हम बोलने से कभी चूकते नहीं। वहीं संतों के विवाद पर बागेश्वर बाबा ने कहा कि हमारी औकात नहीं अभी संतों के विवाद पर बोलने की। क्योंकि अभी हम संत नहीं बन पाए हैं, और बनने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं कब बन पाएंगे।

असम सीएम हिमंता के 'मियां' बयान पर बवाल, हेट स्पीच बताकर जमात पहुंची सर्वोच्च न्यायालय

गुवाहटी। असम में मिया मुसलमानों को निशाना बनाकर कथित रूप से नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में मुख्यमंत्री के बयान को नफरत फैलाने वाला और दो समुदायों के बीच विभाजन पैदा करने वाला बताया गया है। याचिका में असम के मुख्यमंत्री द्वारा 27 जनवरी को दिए गए उस बयान का जिक्र है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर 4 से 5 लाख 'मिया' मतदाताओं को मतदाता सूची से हटाने की बात कही थी। याचिका में मिया शब्द के आपत्तिजनक प्रयोग का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें तर्क दिया गया है कि असम में इस शब्द का प्रयोग मुसलमानों के विरुद्ध अपमानजनक तरीके से किया जाता है। जमीयत ने सर्वोच्च न्यायालय से असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश देने की अपील की है ताकि भविष्य में कोई भी संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति इस तरह के बयान न दे सके।

सरमा ने तीखा बयान देते हुए कहा कि

जब तक वह मुख्यमंत्री रहेंगे, 'मिया' समुदाय के लोगों को 'मुसीबत' का सामना करना पड़ेगा। सरमा ने यहां तक कह दिया कि अगर 'मिया' समुदाय के लोगों के लिए काफी परेशानियां खड़ी की गईं, तो वे राज्य छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। असम में बंगाली भाषी मुसलमानों के लिए आमतौर पर 'मिया' शब्द का प्रयोग किया जाता है। सरकारी कार्यक्रम में पत्रकारों से बात करते हुए सरमा ने कहा, 'अगर मैं असम में रहा, तो उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ेगा।'

उन्होंने आगे कहा, 'वे यहां शांति से नहीं रह सकते। अगर हम उनके लिए परेशानियां खड़ी करेंगे, तभी वे राज्य छोड़ेंगे।

सरमा ने दावा किया कि 'मिया' 'अवैध बांग्लादेशी' हैं और उन्हें राज्य में काम करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने भारत के मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी हस्तक्षेप करने का आग्रह किया और उनके बयानों को 'मुस्लिम विरोधी, खतरनाक और विभाजनकारी' बताया। एआईएमपीएलबी के बयान में कहा गया, 'भारत के मुख्य न्यायाधीश से तत्काल हस्तक्षेप करने का आग्रह किया गया है।

चंद्रबाबू नायडू को ईडी से मिली क्लीन चिट, चार्जशीट से नाम हटाया

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कौशल विकास निगम मामले में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को क्लीन चिट देते हुए कहा है कि कथित अपराध में उनकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संलिप्तता नहीं है। विशाखापत्तनम स्थित विशेष पीएमएलए न्यायालय में 31 जनवरी को दायर पूरक आरोपपत्र में ईडी ने कहा कि नायडू को मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़ने वाला कोई सबूत नहीं है और उन्हें इस मामले में आरोपी के रूप में नामित नहीं किया है। इससे पहले, आंध्र प्रदेश आपराधिक जांच विभाग (एपी सीआईडी) ने भी पुष्टि की थी कि नायडू कौशल विकास परियोजना से संबंधित कथित अनियमितताओं में शामिल नहीं थे। विजयवाड़ा एसीबी कोर्ट ने मामले को वापस लेने की अनुमति देते हुए आगे स्पष्ट किया था कि आरोपों को साबित करने का कोई आधार नहीं है।

कौशल विकास मामले के चलते नायडू को सितंबर 2023 में गिरफ्तार किया गया था। जमानत मिलने से पहले उन्होंने राजामंड्री सेंट्रल जेल में 53 दिनों से अधिक समय बिताया था। अक्टूबर 2023 में उन्हें जमानत मिल गई थी। ईडी की नवीनतम खोज इस हाई-प्रोफाइल मामले में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। यह मामला आंध्र प्रदेश राज्य कौशल विकास निगम (झएएञ) से कथित तौर पर धन के दुरुपयोग से संबंधित है, जिसके कारण राज्य सरकार को 300 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। नायडू ने किसी भी प्रकार की त्रुटि से इनकार किया है और अपने खिलाफ दर्ज मामलों को लेकर राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाया है।

अजित पवार की मौत पर कांग्रेस का सनसनीखेज दावा, विजय वडेट्टीवार बोले- 80% को साजिश का शक

दिव्यांश

मुंबई।कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने सोमवार को महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार की विमान दुर्घटना में हुई मौत के पीछे षड्यंत्र होने का संकेत दिया। उन्होंने कहा कि राज्य के 80 प्रतिशत लोगों का मानना है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। विजय वडेट्टीवार ने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) को इस मामले की जांच की मांग करनी चाहिए। उन्होंने एनसीपी प्रमुख अजीत पवार की मृत्यु के कुछ ही दिनों बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार के उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर भी सवाल उठाए और कहा कि हर कोई सत्ता हथियाने की होड़ में लग गया।

वडेट्टीवार ने कहा कि महाराष्ट्र के 80% लोगों का मानना है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। केवल सीआईडी जांच से कुछ हल नहीं होगा। आखिरी समय में पायलट क्यों बदला गया? इतने बड़े नेता के मामले में लापरवाही कैसे हो सकती है। एनसीपी नेताओं को प्रधानमंत्री मोदी से इसकी जांच कराने की मांग करनी चाहिए... अगर यह दुर्घटना नहीं है, अगर इसके पीछे कोई षड्यंत्र है, तो यह किसकी ओर इशारा करता है?

उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई इस

तरह की बातें कर रहा है, तो उसे यह भी बताना चाहिए कि वह किसकी ओर इशारा कर रहा है... अजित दादा की मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार भी पूरा नहीं हुआ था कि सब सत्ता हथियाने की होड़ में जुट गए। इससे पहले, शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने अजीत पवार की मृत्यु पर 'संदेह' जताते हुए कहा कि भाजपा ने एनसीपी प्रमुख को सिंचाई घोटाले की फाइलों से धमकाया था, जब उन्होंने विलय की इच्छा व्यक्त की थी। उन्होंने यह भी कहा कि महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री की '10 दिनों के भीतर रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई।'

संजय राउत ने कहा कि अजित दादा की दुर्घटना पर सवाल जरूर उठेंगे; सवाल उठने ही चाहिए। जिस तरह से अजीत पवार जैसे महाराष्ट्र के दिग्गज नेता की विमान दुर्घटना में मृत्यु हुई और जो तथ्य सामने आ रहे हैं - इसकी जांच होनी चाहिए, मुझे लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। ये सवाल अजीत दादा की पार्टी उठा रही है। उनकी मृत्यु संदिग्ध है। 66 वर्षीय अजित पवार का 28 जनवरी की सुबह पुणे जिले के बारामती हवाई अड्डे पर उतरने की कोशिश के दौरान विमान दुर्घटना में निधन हो गया। मृतकों में उनके निजी सुरक्षा अधिकारी, एक फ्लाइट अटेंडेंट और दो पायलट शामिल थे। हालांकि, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) के प्रमुख शरद पवार ने लोगों से अपने भतीजे अजीत पवार की मृत्यु का राजनीतिकरण न करने का आग्रह करते हुए कहा है कि विमान दुर्घटना एक हादसा था।

राउत ने अजित पवार की मौत पर खड़े किए सवाल

बीजेपी 'घोटाले वाली फाइल' का किया जिक्र, भाजपा बोला- बेबुनियाद आरोप

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

संजय राउत ने सोमवार को कहा कि पूर्व महाराष्ट्र उपमुख्यमंत्री अजित पवार द्वारा भाजपा के कथित घोटाले से जुड़ी एक फाइल होने का दावा करने के कुछ ही दिनों बाद एक हादसे में मारे गए। उन्होंने घटनाक्रम को रहस्यमयी बताते हुए मौत पर सवाल खड़े किए।

अजित के पास भाजपा के खिलाफ फाइल थी- राउत

दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने यह भी दावा किया कि अजित पवार ने भाजपा से नाता तोड़ने और अपने चाचा व शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी (एसपी) में लौटने का फैसला कर लिया था। अजित पवार लगातार कहते रहे कि उनके पास भाजपा के घोटाले की फाइल है और वे इसका खुलासा करेंगे। 15 जनवरी को उन्होंने यह बात कही और अगले दस दिनों में एक दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। यह रहस्यमय है। बता दें कि अजित पवार की 28 जनवरी को बारामती में विमान हादसे में मौत हो गई थी।

'दादा शरद पवार के साथ लौटना चाहते थे'

आपको बताते चलें कि नगर निकाय चुनाव प्रचार के दौरान अजित पवार ने दावा किया था कि 1995 से 1999 के बीच राज्य में सत्ता में रही भाजपा और अविभाजित शिवसेना के दौर के कथित भ्रष्टाचार से जुड़ी एक फाइल उनके पास है। राउत ने कहा, जिस दिन अजित पवार ने भाजपा घोटाले की फाइल होने की बात कही, उसी दिन से मुझे शक था। इसका मतलब था कि अजित दादा ने भाजपा से दूरी बनाने का मन बना लिया था और वे फिर से शरद पवार के साथ लौटना चाहते थे।

शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद राउत ने यह भी कहा कि भले ही शरद पवार ने साफ कर दिया हो कि अजित पवार की मौत एक दुर्घटना थी और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन समय के साथ वे भी समझेंगे कि मामला उतना सरल नहीं है।

राउत ने सवाल उठाते हुए कहा, अजित पवार जैसे नेता विमान में बैठते हैं और उसमें कोई अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं होता, न उनके साथ ओएसडी होता है, न मेंटेनेंस सर्टिफिकेट। उन्होंने दावा किया कि अजित पवार का अपने मूल घर लौटना भाजपा के लिए बड़ी हार होती और यह देश की राजनीति में निर्णायक मोड़ साबित होता। राउत ने यह भी कहा कि अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अब भाजपा की जागीर बनकर रह गई है।

राउत के आरोपों पर भाजपा का पलटवार

राउत के आरोपों पर भाजपा की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई। भाजपा एमएलसी चित्रा वाघ ने कहा कि राउत अपने हितों के लिए किसी की मौत का इस्तेमाल कर रहे हैं और बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। चित्रा वाघ ने कहा, अगर अजित पवार के पास भाजपा के खिलाफ कोई दस्तावेज थे और वे नष्ट नहीं हुए हैं, तो उन्हें खोजा जाना चाहिए। राउत अदालत जाने के लिए स्वतंत्र हैं। उन्होंने तंज कसते हुए यह भी कहा कि राउत चाहें तो अंतरराष्ट्रीय अदालत भी जा सकते हैं, क्योंकि उन्हें भारतीय संस्थाओं पर भरोसा नहीं है।

रतलाम मंडल के 07 रेलकर्मी विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

02 फरवरी, 2025 को मुम्बई के यशवंत राव चाव्हान प्रतिष्ठान, मुम्बई में पश्चिम रेलवे चर्चगेट कार्यालय द्वारा 70वां रेल सप्ताह के अंतर्गत विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया । इस दौरान महाप्रबंधक पश्चिम रेलवे श्री प्रदीप कुमार द्वारा पश्चिम रेलवे के विभिन्न मंडलों, उत्पादन एवं निर्माण इकाइयों के कुल 92 अधिकारियों एवं कर्मचारियों जिसमें रतलाम मंडल के 07 रेल कर्मियों को वर्ष 2025 में अपने-अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए एफिसियंसी मेडल एवं मेरिट सर्टिफिकेट प्रदान कर सम्मानित किया गया। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी श्री मुकेश कुमार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार महाप्रबंधक पश्चिम रेलवे द्वारा पुरस्कृत होने वालों में रतलाम मंडल के कर्मचारियों में सुश्री अंजू कटियार - वरिष्ठ खंड अभियंता (बिजली/डीजल), विद्युत विभाग; श्री दिनेश कुमार मोतीलाल - लोको पायलट (शंटर)-घ्ट, विद्युत विभाग; श्री मनीष धोबी - वरिष्ठ खंड अभियंता (पी-वे), निर्माण विभाग; श्री पियूष जोशी - वरिष्ठ क्लर्क कम टाइपिस्ट, स्थापना विभाग; श्री प्रकाश टेलर - कनिष्ठ अभियंता, यांत्रिक विभाग; श्री राजकुमार साल्या - वरिष्ठ तकनीशियन (सिग्नल), संकेत एवं दूरसंचार विभाग; एवं श्री अवधेश कुमार - मुख्य कार्यालय अधीक्षक, स्टोर विभाग, रतलाम शामिल हैं। विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार मिलने पर मंडल रेल प्रबंधक श्री अश्वनी कुमार ने उपरोक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देते हुए सभी अधिकारियो एवं कर्मचारियों से अपील की है कि वो अपने-अपने क्षेत्र के कार्यों को पूरी तन्मयता एवं कर्मठता के साथ करें ताकि मंडल के अधिक से अधिक अधिकारियों एवं कर्मचारियो को मंडल, जोनल एवं रेलवे बोर्ड स्तर पर सम्मान प्राप्त हो तथा रतलाम मंडल सतत विकास के पथ पर आगे बढ़ता रहे।

पश्चिम रेलवे का 70वाँ रेल सप्ताह समारोह

महाप्रबंधक श्री प्रदीप कुमार द्वारा 92 कर्मचारियों को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 'विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार' से सम्मानित किया गया

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

पश्चिम रेलवे के 70वें रेल सप्ताह समारोह के अंतर्गत विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025 का आयोजन सोमवार, 02 फरवरी, 2026 को यशवंतराव चव्हाण सभागार, मुंबई में किया गया। इस अवसर पर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक (प्रभारी) प्रदीप कुमार ने पश्चिम रेलवे के 92 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनकी उत्कृष्ट एवं सराहनीय सेवाओं के लिए व्यक्तिगत पुरस्कार विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार प्रदान किए।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह पुरस्कार समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, जिसका उद्देश्य पश्चिम रेलवे के उन अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कड़ी मेहनत, समर्पण और प्रतिबद्धता को सम्मानित करना होता है, जो सदैव चुनौतियों का सामना करने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे सक्षम एवं कर्मठ अधिकारियों एवं कर्मचारियों में से चयनित कर्मियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाता है। यह पुरस्कार न केवल अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करता है, बल्कि अन्य कर्मचारियों को भी आगामी वर्ष में और अधिक उत्साह एवं समर्पण के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करता है।

इस अवसर पर पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन की अध्यक्षा श्रीमती ईशा मलिक, प्रमुख विभागाध्यक्ष, मंडल रेल प्रबंधक, मुख्य कारखाना प्रबंधक एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। अपने संबोधन में पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक (प्रभारी) श्री प्रदीप कुमार ने सभी पुरस्कार विजेताओं को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों एवं संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति में दिए गए योगदान के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि पश्चिम रेलवे अपने सभी कर्मचारियों के समर्पित प्रयासों के कारण अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल कर सका है।

श्री प्रदीप कुमार ने पश्चिम रेलवे की हाल की विभिन्न उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कर्मचारियों से रेलवे तथा राष्ट्र की समग्र प्रगति के लिए अपना सर्वोत्तम योगदान देने का आह्वान किया। इस अवसर पर महाप्रबंधक श्री प्रदीप कुमार ने वर्ष के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रमुख विभागाध्यक्षों/मंडल रेल प्रबंधकों/मुख्य कारखाना प्रबंधकों को स्मृति-चिह्न प्रदान कर सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने 'अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार' 2025 के उन सात व्यक्तिगत पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को भी सम्मानित किया, जिन्हें हाल ही में नई दिल्ली में संपन्न राष्ट्रीय रेल सप्ताह समारोह के दौरान माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव द्वारा यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया था।

इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में पश्चिम रेलवे की मुख्य कार्मिक अधिकारी (आईआर) श्रीमती प्रमिला सिंह ने अतिथियों का स्वागत किया तथा उप महाप्रबंधक (सामान्य) द्वारा धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया गया।

रेल मंत्री द्वारा महाराष्ट्र के लिए रिकॉर्ड 23,926 करोड़ के रेल बजट आवंटन की जानकारी मीडिया को दी गई

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने बजट वर्ष 2026-27 में महाराष्ट्र राज्य को प्रदान किए गए रिकॉर्ड रेल बजट आवंटन की जानकारी मीडिया प्रतिनिधियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र को ?23,926 करोड़ रुपये का ऐतिहासिक रेल बजट आवंटित किया गया है, जो राज्य में रेल अवसंरचना के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

महाराष्ट्र राज्य में रेलवे अवसंरचना के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा ऐतिहासिक स्तर पर बजट आवंटन किया गया है। वर्ष 2009-14 की तुलना में वर्ष 2026-27 के दौरान रेलवे के लिए वार्षिक औसत बजट में लगभग 20 गुना की वृद्धि दर्ज की गई है।

वार्षिक औसत बजट (2009-14): 1,171 करोड़

वार्षिक औसत बजट (2026-27): 23,926 करोड़

अवसंरचना में व्यापक परिवर्तन

महाराष्ट्र में वर्तमान में 1,70,058 करोड़ की लागत के रेलवे कार्य प्रगति पर हैं। इस विशाल निवेश के अंतर्गत नई रेल लाइनों का निर्माण, स्टेशनों का पुनर्विकास तथा सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं, जिससे पूरे राज्य में

रेलवे सेवाओं का कायाकल्प हो रहा है।

अमृत स्टेशन योजनाः यात्री सुविधाओं में नया आयाम

यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र के 132 स्टेशनों को अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकास हेतु चिन्हित किया गया है।

कुल निवेशः 5,675 करोड़

पूर्ण हुए स्टेशन (17): लासलगांव, चिंचपोकली (फेज-1), देवलाली, परेल, सावदा, धुले, वडाला रोड, माटुंगा, केडगांव, लोणंद जं., मूर्तिजापुर जं., शाहद, चांदा फोर्ट (फेज-1), आमगांव (फेज-1), नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी जं. (फेज-1), बारामती एवं नांदुरा।

बेहतर कनेक्टिविटी

राज्य में प्रीमियम ट्रेनों के विस्तार से यात्रा अनुभव में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वंदे भारत एक्सप्रेसः 12 जोड़ी सेवाएँ संचालित

अमृत भारत एक्सप्रेसः 5 जोड़ी सेवाएँ संचालित

नेटवर्क विस्तार एवं 100ः विद्युतीकरण

नई रेल लाइन निर्माणः वर्ष 2014 से अब तक लगभग 2,400 किलोमीटर नई पटरियों का निर्माण, जो मलेशिया के संपूर्ण रेल नेटवर्क से भी अधिक है।

पूर्ण विद्युतीकरणः 2014 के बाद 3,744 किलोमीटर रेल मार्गों का विद्युतीकरण कर महाराष्ट्र को 100ः विद्युतीकृत राज्य बनाया गया।

फ्लाईओवर एवं अंडरपासः 1,228

फ्लाईओवर एवं अंडरपास का निर्माण।

सुरक्षा में मजबूती - 'कवच' प्रणाली

रेलवे सुरक्षा को और सुदृढ़ करने हेतु 'कवच' स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का कार्य तेज़ी से आगे बढ़ रहा है।

कवच (रूट किलोमीटर में):

कुल स्थानः576

कार्य पूर्ण / टेंडर प्रगति परः 3617 रूट किलोमीटर

कुल स्वीकृतः 4,981 रूट किलोमीटर

इन सभी पहलों के माध्यम से महाराष्ट्र में रेलवे अवसंरचना, यात्री सुविधाओं, कनेक्टिविटी और सुरक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक परिवर्तन सुनिश्चित किया जा रहा है। पुनीत अग्रवाल मंडल रेल प्रबंधक, भुसावल मंडल एवं वरिष्ठ शाखा अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान मौजूद थे।

ठाणे-कल्याण-डोंबिवली-उल्हासनगर में मेयर पद पर शिवसेना का दावा, महिला प्रत्याशी नामित

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने ठाणे, कल्याण-डोंबिवली और उल्हासनगर नगर निगमों में मेयर पद के लिए महिला उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। इन पदों पर कोई आरक्षण नहीं है, फिर भी पार्टी ने महिलाओं पर भरोसा जताया है। एकनाथ शिंदे ने सोमवार को इसकी जानकारी दी।

इन महिला नेताओं को मिलेगी कमान

एकनाथ शिंदे के कार्यालय से जारी एक बयान में बताया गया कि ठाणे नगर निगम में शर्मिला पिंपोलकर-गायकवाड को मेयर पद के लिए नामित किया जाएगा। वहीं, कल्याण-डोंबिवली नगर निगम में हर्षाली थाविल चौधरी और उल्हासनगर नगर निगम में अश्विनी निकम को यह जिम्मेदारी दी जाएगी। यह इन नगर निगमों के इतिहास में पहली बार होगा जब बिना आरक्षण के कोई महिला मेयर का पद संभालेगी।

आरक्षण से आगे बढ़कर मौका देने की पहल

पार्टी ने कहा कि यह फैसला सोच-समझकर लिया गया है, ताकि अनिवार्य कोटे से आगे बढ़कर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा सके। बयान में कहा गया, 'महिलाओं को आरक्षण का इंतजार किए बिना उनकी क्षमता और नेतृत्व के आधार पर अवसर मिलने चाहिए।' शिवसेना ने यह भी कहा कि जब इन पदों पर किसी तरह का आरक्षण नहीं था, तो पुरुष मेयर चुने जाने की अटकलें थीं, लेकिन पार्टी ने अपनी बहनों पर भरोसा जताया है।

श्रीकांत शिंदे ने की थी वकालत

बयान के अनुसार, कल्याण से शिवसेना सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे ने इस बात की वकालत की थी कि सक्षम महिला पार्षदों को शीर्ष नागरिक पद के लिए मौका दिया जाना चाहिए। उनके प्रस्ताव को एकनाथ शिंदे ने मंजूरी दी। पार्टी ने यह भी बताया कि बृहन्मुंबई नगर पालिका में शिवसेना के 29 पार्षदों में से 19 महिलाएं हैं।

मोहम्मद अली मार्ग एवं इब्राहिम मर्चेंट मार्ग पर फुटपाथों पर किए गए अनधिकृत फेरीवालों और अतिरिक्त निर्माणों को हटाया गया

मुंबई । मुंबई के अत्यंत व्यस्त वाणिज्यिक मार्गों में शामिल मोहम्मद अली मार्ग तथा इब्राहिम मर्चेंट मार्ग क्षेत्र में फुटपाथों पर किए गए अनधिकृत अतिरिक्त निर्माणों और अवैध फेरीवालों को आज (दिनांक 2 फरवरी 2026) बृहन्मुंबई महानगरपालिका के 'बी' प्रशासनिक विभाग द्वारा हटाया गया।

यह कार्रवाई अतिरिक्त आयुक्त (शहर) डॉ. (श्रीमती) अश्विनी जोशी के निर्देशानुसार, उप आयुक्त (ज़ोन-1) श्रीमती चंदा जाधव के मार्गदर्शन में तथा सहायक आयुक्त (बी विभाग) श्री योगेश देसाई के नेतृत्व में की गई।

मोहम्मद अली मार्ग भेंडी बाज़ार, मस्जिद बंदर और बायकुला क्षेत्रों को जोड़ने वाला एक प्रमुख मार्ग है, जबकि इब्राहिम मर्चेंट मार्ग नागदेवी और मंडवी क्षेत्र के समीप स्थित है। ये दोनों सड़कें व्यापार एवं यातायात की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों मार्गों के फुटपाथों पर अनधिकृत निर्माण पाए गए थे। इसके साथ ही, इस क्षेत्र में अवैध फेरीवालों द्वारा दुकानें लगाए जाने की भी जानकारी सामने आई। इससे वाहन चालकों की आवाजाही तथा पैदल यात्रियों के चलने में बाधा उत्पन्न हो रही थी।

इसी पृष्ठभूमि में, बृहन्मुंबई महानगरपालिका के 'बी' प्रशासनिक विभाग द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस अभियान के अंतर्गत फुटपाथों पर किए गए अनधिकृत फेरीवालों और अवैध निर्माणों को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान 7 अनधिकृत दुकानों को हटाया गया। साथ ही 12 ओटले, शीट लोहे के शेड, 10 बोलार्ड तथा 2 लावारिस वाहनों के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई।

यह अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई 04 अतिक्रमण हटाने वाले वाहनों, 02 जेसीबी मशीनों एवं अन्य आवश्यक उपकरणों की सहायता से की गई। इस दौरान महानगरपालिका के 40 अधिकारी एवं कर्मचारी, साथ ही पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया था।

इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय नागरिकों ने संतोष व्यक्त किया है। महानगरपालिका प्रशासन ने जानकारी दी है कि अनधिकृत एवं बढ़े हुए निर्माणों के विरुद्ध ऐसी नियमित कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

पश्चिम रेलवे - भावनगर मंडल

विभिन्न इंजीनियरिंग कार्य

निविदा सं: 263-2025-26 से 265-2025-26

सं	ई-निविदा सं.	कार्य का नाम	निविदा मूल्य(रु.)	ईएमडी रु.
1	263-2025-26	भावनगर टर्मिनस (BVC) यार्ड का रीमॉडलिंग और इंटरलॉकिंग में सुधार।	24,70,31,566.21	13,85,200.00
2	264-2025-26	डीईएन(डब्ल्यू) क्षेत्राधिकार: भूमि योजनाओं का प्रमाणीकरण, सर्वेक्षण संख्याओं के साथ अधिरोपण तथा केएनएलएस-डब्ल्यूएसजे के लापता भूमि योजना का पुनर्गठन।	19,51,763.37	39,000.00
3	265-2025-26	भावनगर मंडल के स्वीकृत कार्य के तहत DEN-पश्चिम सेक्शन में 7 स्टेशनों पर EI भवनों का प्रावधान, जिसमें मौजूदा PI स्टेशनों को EI, MSDAC और इन-बिल्ट ब्लॉक वर्किंग के साथ कोड-लाइफ-आधारित प्रतिस्थापन, जिसमें 19 स्टेशनों पर संबंधित सिग्नलिंग और दूरसंचार उपकरण शामिल हैं।	13,26,03,737.33	8,13,000.00

उपरोक्त सभी निविदाओं के लिए: बिडिंग प्रारंभ तिथि: 09/02/2026 **बिडिंग समाप्ति तिथि:** 23/02/2026 एनआईटी रेलवे की **वेबसाइट** www.ireps.gov.in **पर दिनांक - 30/01/2026** को अपलोड कर दी गई है। BVP 256

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly • हमें फॉलो करें: twitter.com/WesternRly

पश्चिम रेलवे वडोदरा मंडल

ईएल (इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग) सिस्टम का व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध (CAMC)

निविदा सूचना संख्या: S&T/BRC/25-26/39/SIG दिनांक: 30-01-2026 भारत के राष्ट्रपति की ओर से और उनके लिए, सीनियर डीएसटीई/वडोदरा, निविदा संख्या S and T _BRC_25-26_39_ SIG के लिए ई-टेंडर आमंत्रित करते हैं। बोली लगाने वाले अपनी मूल/संशोधित बोलियाँ केवल अंतिम तिथि और समय तक ही जमा कर पाएंगे। इस टेंडर के लिए मैनुअल ऑफ़र स्वीकार नहीं किए जाएंगे, और ऐसा कोई भी मैनुअल ऑफ़र मिलने पर उसे नज़रअंदाज़ कर दिया जाएगा। **1. कार्य का नाम और स्थान:** वडोदरा मंडल में वडोदरा यार्ड, अंकलेश्वर, छावज और पनोली स्टेशनों पर 03 साल के लिए ईएल (इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग) सिस्टम (एम/एस सीमेंस मेक) का व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध (CAMC)। **2. कार्य की अनुमानित लागत:** ₹ 1,78,66,023.48 **3. जमा की जाने वाली बयाना राशि:** ₹ 2,39,300.00 **4. ई-निविदा जमा करने और ई-निविदा खोलने की तारीख और समय:** 23.02.2026 @ 15:00 बजे और 23.02.2026 @ 15:30 बजे **5. वेबसाइट का विवरण और नोटिस का स्थान जहाँ पूरी जानकारी देखी जा सकती है आदि:** सीनियर डिविजनल सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर, दूसरी मंजिल-एनेक्स बिल्डिंग, डीआरएम कार्यालय, पश्चिम रेलवे, प्रतापनगर, वडोदरा-390004 http://www.ireps.gov.in BRC 339

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly

महाराष्ट्र की सियासत में नया अध्याय, उपमुख्यमंत्री के बाद अब सुनेत्रा पवार बनेंगी एनसीपी की बॉस!

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार सोमवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभाल सकती हैं। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्ति की औपचारिक प्रक्रिया के अनुसार, आगामी दिनों में अंतिम निर्णय लिए जाने की उम्मीद है। इस प्रक्रिया पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आगामी बैठक में चर्चा की जाएगी। यह घटनाक्रम एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री रहे अजीत पवार (66) के निधन के कुछ दिनों बाद सामने आया है। अजीत पवार का 28 जनवरी को उनके गृह नगर बारामती में एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया था, जिसके बाद पार्टी के भावी नेतृत्व और राजनीतिक दिशा को लेकर अटकलें तेज हो गई थीं।

अजित पवार के अचानक निधन के बाद, एनसीपी के वरिष्ठ नेता सुनेत्रा पवार के समर्थन में एकजुट हो गए हैं और पार्टी नेतृत्व से उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त करने का आग्रह कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, संगठन के भीतर उनकी पदोन्नति के पक्ष में आम सहमति बन रही है। एकजुटता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण पेश करते हुए, एनसीपी के 30 से अधिक प्रमुख पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय कार्यकारी

अध्यक्ष प्रफुल पटेल और महाराष्ट्र एनसीपी अध्यक्ष सुनील तटकरे को एक संयुक्त पत्र लिखा है। पत्र में सर्वसम्मति से मांग की गई है कि सुनेत्रा पवार को पार्टी का सर्वोच्च संगठनात्मक पद सौंपा जाए। यह कदम एनसीपी के लिए एक महत्वपूर्ण समय पर आया है, क्योंकि हाल के उथल-पुथल के बाद वह अपनी संगठनात्मक संरचना को मजबूत करने और राज्यों में अपनी राजनीतिक उपस्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास कर रही है।

सुनेत्रा पवार ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली

62 वर्षीय सुनेत्रा पवार ने शनिवार को मुंबई के लोक भवन में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। उन्हें आबकारी विभाग, खेल एवं युवा कल्याण विभाग और अल्पसंख्यक कल्याण एवं विकास विभाग आवंटित किए गए हैं - ये विभाग पहले अजीत पवार के पास थे। अजीत पवार का 28 जनवरी को बारामती में विमान दुर्घटना में निधन हो गया था। वे महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री थे।

7 फरवरी को जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के लिए मतदान

उद्योगों, प्रतिष्ठानों और कारखानों में कर्मचारियों को पूर्ण वेतन सहित अवकाश

मुंबई।राज्य में शनिवार, 7 फरवरी 2026 को 12 जिला परिषदों तथा उनके अंतर्गत 125 पंचायत समितियों के लिए आम चुनाव कराए जा रहे हैं। इस चुनाव में राज्य के सभी मतदाताओं तथा राज्य की सीमा से लगे क्षेत्रों में कार्यरत मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर मिल सके, इसके लिए उस दिन उद्योगों, प्रतिष्ठानों और कारखानों में कार्यरत कर्मचारियों को अवकाश अथवा रियायत देना अनिवार्य किया गया है। यह जानकारी उद्योग, ऊर्जा, श्रम एवं खान विभाग द्वारा जारी परिपत्र में दी गई है।

इसके अनुसार, मतदान क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता कर्मचारियों तथा कार्य के कारण मतदान क्षेत्र से बाहर कार्यरत मतदाता अधिकारियों/कर्मचारियों को चुनाव के दिन पूर्ण वेतन सहित अवकाश देने के निर्देश दिए गए हैं। यह अवकाश उद्योग, ऊर्जा और श्रम विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी प्रतिष्ठानों, कारखानों, दुकानों आदि पर लागू होगा। यह आदेश निजी कंपनियों, सभी दुकानों व अन्य प्रतिष्ठानों, आवासीय होटल, भोजनालय, लॉजिंग हाउस, थिएटर, व्यापारिक एवं औद्योगिक उपक्रम, सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियाँ, शॉपिंग सेंटर, मॉल, रिटेलर आदि सभी पर समान रूप से लागू रहेगा।

विशेष परिस्थितियों में, यदि खतरनाक कार्य, जनसेवा से जुड़े प्रतिष्ठान, अथवा ऐसे प्रतिष्ठान जहाँ कर्मचारियों की अनुपस्थिति से गंभीर क्षति हो सकती है, वहाँ यदि पूर्ण दिवस का अवकाश देना संभव न हो, तो संबंधित प्रतिष्ठान के मालिकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कर्मचारियों, अधिकारियों एवं श्रमिकों को मतदान के लिए दो से तीन घंटे की विशेष छूट अवकाश के स्थान पर दी जाए।

जिन जिला परिषद क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश लागू रहेगा, वे इस प्रकार हैं–

रायगढ़ (पंचायत समितियाँः पनवेल, कर्जत, खालापुर, सुधागड, पेण, उरण, अलीबाग, मुरुड, रोहा, तळा, माणगांव, म्हसळा, श्रीवर्धन, महाड, पोलादपुर)

रत्नागिरी (मंडणगड, दापोली, खेड़, चिपळूण, गुहागर, रत्नागिरी, संगमेश्वर, लांजा, राजापुर)

सिंधुदुर्ग (वैभववाड़ी, कणकवली, देवगड, मालवण, कुडाळ, वेंगुर्ला, सावंतवाड़ी, दोडामार्ग)

पुणे (जुन्नर, आंबेगांव, शिरूर, खेड़, मावळ, मुळशी, हवेली, दौंड, पुरंदर, वेल्हे, भोर, बारामती, इंदापुर)

सातारा (खंडाला, फलटण, मान, खटाव, कोरेगांव, वाई, महाबळेश्वर, जावळी, सातारा, पाटन, कराड)

सांगली (आटपाडी, जत, खानापुर (विटा), कडेगांव, तासगांव, कवठेमहांकाळ, पलूस, वाळवा-ईश्वरपूर, शिराळा, मिरज)

सोलापुर (करमाळा, माढा, बार्शी, उत्तर सोलापुर, मोहोळ, पंढरपूर, माळशिरस, मंगळवेढा, सांगोला, दक्षिण सोलापुर, अक्कलकोट)

कोल्हापुर (शाहूवाडी, पन्हाळा, हातकणंगले, शिरोळ, कागल, करवीर, गगनबावडा, राधानगरी, भुदरगड, आजरा, गडहिंग्लज, चंदगड)

छत्रपति संभाजीनगर (सोयगांव, सिल्लोड, कन्नड, फुलंब्री, खुल्ताबाद, वैजापुर, गंगापुर, छत्रपति संभाजीनगर, पैठण)।

ग्रेटर मुंबई क्षेत्र में सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 250 रुपये जुर्माना

कचरा फेंकने पर 500 रुपये, गीले व सूखे कचरे का पृथक्करण न करने पर 200 रुपये

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबईः बृहन्मुंबई महानगरपालिका द्वारा ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं संचालन), स्वच्छता एवं स्वास्थ्य उपविधियाँ-2025 जारी की जा रही हैं। इनमें कचरा उत्पन्न करने वालों, विभिन्न प्रतिष्ठानों, कचरा सेवा प्रदाताओं; ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन, भंडारण, वितरण एवं प्रसंस्करण आदि से संबंधित विस्तृत नियम शामिल हैं। इन नियमों का उल्लंघन करने पर नागरिकों अथवा प्रतिष्ठानों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके अंतर्गत सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 250 रुपये, कचरा फेंकने पर 500 रुपये, गीले व सूखे कचरे का पृथक्करण न करने पर 200 रुपये, तथा बिना लाइसेंस कचरा परिवहन करने पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

बृहन्मुंबई महानगरपालिका के आयुक्त एवं प्रशासक श्री भूषण गगराणी के निर्देशानुसार, अतिरिक्त आयुक्त (शहर) डॉ. (श्रीमती) अश्विनी जोशी के मार्गदर्शन तथा उप आयुक्त (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन) श्री किरण दिघावकर के पर्यवेक्षण में, बृहन्मुंबई (मुंबई शहर एवं उपनगर) क्षेत्र को स्वच्छ रखने हेतु नियमित कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही समय-समय पर विशेष स्वच्छता अभियान एवं गतिविधियाँ भी आयोजित की जाती हैं। इसी संदर्भ में ये उपविधियाँ जारी की जा रही हैं।

अतिरिक्त आयुक्त (शहर) डॉ. (श्रीमती) अश्विनी जोशी ने बताया कि बृहन्मुंबई महानगरपालिका का ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विभाग मुंबई महानगर क्षेत्र (शहर एवं उपनगर) में ठोस कचरे के प्रभावी प्रबंधन के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस उद्देश्य से, मुंबई महानगर क्षेत्र में उत्पन्न अथवा लाए गए गीले व सूखे कचरे के वर्गीकरण एवं प्रसंस्करण से संबंधित सभी विषयों के विनियमन तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 के संदर्भ में, ये उपविधियाँ-2025 जारी की जा रही हैं।

प्राकृतिक तेल और गैस की बचत राष्ट्रीय सेवा है– मंत्री मंगलप्रभात लोढ़ा

'सक्षम 2025-26' ऊर्जा संरक्षण अभियान आज से प्रारंभ

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

प्राकृतिक तेल और गैस की बचत करना देश की सेवा है। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में ईंधन संरक्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रमुख उद्देश्य है और सभी की सहभागिता से देश इस लक्ष्य को प्राप्त करेगा। तेल और गैस का संरक्षण अर्थात हरित ऊर्जा को अपनाना है तथा इस सामाजिक दायित्व अभियान में सभी को भाग लेना चाहिए–यह अपील कौशल, रोजगार, उद्यमिता एवं नवाचार मंत्री मंगलप्रभात लोढ़ा ने की।

केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मार्गदर्शन में तथा राज्य सरकार के सहयोग से, प्रभादेवी स्थित रविंद्र नाट्य मंदिर में तेल उद्योग के राज्य स्तरीय समन्वयकों द्वारा विभिन्न जनजागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। इसी अंतर्गत 'सक्षम 2025-26 (संरक्षण क्षमता महोत्सव)' का उद्घाटन मंत्री मंगलप्रभात लोढ़ा की अध्यक्षता में किया गया। वे इस अवसर पर संबोधित कर रहे थे।

इस अवसर पर महाराष्ट्र राज्य के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के राज्य स्तरीय समन्वयक उमेश कुलकर्णी, बीपीसीएल पश्चिम क्षेत्र (रिटेल) प्रमुख थॉमस जेम्स, एमएच-1 एवं गोवा, बीपीसीएल राज्य प्रमुख (रिटेल) मिहिर जोशी, एचपीसीएल के उपमहाप्रबंधक वरुण कुमार, आईओसीएल के महाप्रबंधक देवांशु मिश्रा, गेल इंडिया लिमिटेड के महाप्रबंधक (मार्केटिंग) जितेंद्र गुप्ता, राज्य समन्वय विभाग के मुख्य प्रबंधक दीपक वाघ, वरिष्ठ प्रबंधक रितेश जाधव, विद्यालयों के छात्र तथा राज्यभर के विभिन्न ईंधन वितरक उपस्थित थे।

मंत्री लोढ़ा ने कहा कि राज्य तेल एवं गैस समन्वय विभाग द्वारा संचालित इस अभियान का उद्देश्य जीवाश्म ईंधनों की बर्बादी को कम करना, विदेशी मुद्रा पर बढ़ते बोझ को रोकना तथा ग्रीनहाउस गैसों से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान को घटाना है। आज विश्वभर में ऊर्जा की मांग सर्वोच्च स्तर पर है और वैश्विक राजनीति तेल के इर्द-गिर्द केंद्रित है। ईंधन की बचत करना देश की प्रगति में योगदान देना है। सार्वजनिक परिवहन का अधिकतम उपयोग कर हम तेल की बचत कर सकते हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में राज्य में हरित ऊर्जा को प्राथमिकता दी जा रही है। यदि विद्यालय स्तर पर ही तेल संरक्षण का महत्व समझाया जाए, तो भविष्य में इसका बेहतर उपयोग संभव है। मंत्री लोढ़ा ने यह भी कहा कि तेल बचत में प्रत्येक घटक का छोटा-सा योगदान भी देश की प्रगति में सहायक हो सकता है।

बच्चों में डिजिटल लत पर अध्ययन हेतु विशेषज्ञ टास्क फोर्स गठित करने के निर्देश- सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। बच्चों में बढ़ती डिजिटल लत के कारण उनके मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ रहे दुष्प्रभावों को गंभीरता से लेते हुए राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार ने इस विषय पर गहन अध्ययन कर प्रभावी उपाय सुझाने के लिए विशेषज्ञों की एक टास्क फोर्स गठित करने के निर्देश सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को दिए हैं।

केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा 29 जनवरी 2026 को प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में युवाओं और नाबालिग बच्चों में सोशल मीडिया की बढ़ती लत से उत्पन्न खतरों को रेखांकित किया गया है। सर्वेक्षण में बच्चों के लिए सोशल मीडिया उपयोग की आयु-सीमा निर्धारित करने तथा नाबालिगों को लक्षित डिजिटल विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई है।

आर्थिक सर्वेक्षण की इन सिफारिशों तथा महाराष्ट्र की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रधान सचिव श्री वीरेंद्र सिंह को विशेषज्ञों की टास्क फोर्स गठित करने के संबंध में लिखित निर्देश जारी किए गए हैं।

मंत्री एडवोकेट शेलार ने बताया कि राज्य में 18 वर्ष से कम आयु के लगभग चार करोड़ बच्चे हैं, जिनमें से लगभग तीन करोड़ बच्चे 15 वर्ष से कम आयु के हैं।

ऐसे में बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ा यह विषय अत्यंत गंभीर एवं व्यापक सार्वजनिक महत्व का है।

अपने पत्र में मंत्री शेलार ने इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी के 77वें वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रस्तुत निष्कर्षों का भी उल्लेख किया। सम्मेलन में यह सामने आया कि युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में चिंताजनक वृद्धि हो रही है तथा 50 प्रतिशत से अधिक मानसिक रोगों की शुरुआत 18 वर्ष की आयु से पहले हो जाती है। साथ ही 35 वर्ष से कम आयु वर्ग में इन समस्याओं का अनुपात तेजी से बढ़ रहा है, जिससे रोकथाम के लिए त्वरित उपायों की आवश्यकता स्पष्ट होती है।

आर्थिक सर्वेक्षण की सिफारिशों एवं विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत प्रमाणों के आधार पर राज्य के लिए एक संतुलित, वैज्ञानिक एवं तथ्यपरक नीति तैयार करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को इस विषय का व्यापक अध्ययन करने के निर्देश दिए गए हैं। आवश्यकता पड़ने पर सर्वांगीण अध्ययन के लिए विशेषज्ञ कार्यदल गठित करने को भी कहा गया है।

प्रस्तावित टास्क फोर्स में शिक्षा विशेषज्ञ, मनोचिकित्सक, बाल परामर्शदाता, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ, प्रबंधन विशेषज्ञ, चिकित्सक, विधि विशेषज्ञ तथा संबंधित शासकीय विभागों के अधिकारी शामिल होंगे।

इस कार्यदल के अध्ययन क्षेत्र में बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षण, मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव, डिजिटल प्लेटफॉर्म का संतुलित एवं जिम्मेदार उपयोग, शिक्षा एवं समग्र विकास पर प्रभाव, सांस्कृतिक एवं पारिवारिक पहलू, लिंग आधारित अंतर, ग्रामीण-शहरी भिन्नताएं, सभी आय वर्गों का समावेश, उत्पादकता एवं व्यापक आर्थिक प्रभाव, तथा बच्चों की डिजिटल सुरक्षा से संबंधित राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय ढांचों की समीक्षा शामिल होगी।

डिजिटल युग में बच्चों के सर्वांगीण कल्याण के लिए सरकार द्वारा सक्रिय एवं प्रभावी पहल की आवश्यकता पर बल देते हुए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार ने कहा कि इस चुनौती से निपटने के लिए सूचित, संतुलित और दूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाने का यही उचित समय है।

केन्द्रीय बजट 2026-27 में मध्य प्रदेश को 15,188 करोड़ रूपये का रेल बजट आवंटन

उच्च-गति कनेक्टिविटी, माल ढुलाई और सुरक्षा एवं यात्री सुविधाओं पर विशेष फोकस

रतलाम । माननीय केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने प्रस्तुत बजट में भारतीय रेलवे के लिए किए गए प्रावधानों पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग से चर्चा करते हुए बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विगत 11 वर्षों में रेलवे के विकास के लिए अधिकाधिक बल दिया गया है जिससे रेलवे पर उच्च-गति कनेक्टिविटी, माल ढुलाई और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। केन्द्रीय बजट 2026-27 में भारतीय रेल के लिए 2,93,030 करोड़ रूपए के रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) की योजना बनाई गई है। यह भारतीय रेलवे के लिए अब तक का सबसे अधिक पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) और आवंटन है। रेलवे में संरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए इस बजट में 120 हजार करोड़ रूपए का आंवटन किया गया है।

माननीय रेलमंत्री, श्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश राज्य में रेलवे के निरंतर विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस वर्ष भी मध्य प्रदेश राज्य में रेलवे के विस्तार, सेफ्टी, इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2026-27 के बजट में 15,188 करोड़ रूपए आवंटन किया गया है। श्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मध्य प्रदेश में रेल कार्य बहुत तेजी से हो रहे हैं। राज्य में 1,18,379 करोड़ रूपए की विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत न्यू ट्रैक्स प्रोजेक्ट्स पर कार्य चल रहा है। मध्य प्रदेश में 100 प्रतिशत रेल लाइनों को विद्युतीकरण हो गया है। अमृत स्टेशन योजना के तहत मध्य प्रदेश के 80 रेलवे स्टेशनों को रूपये 3,163 करोड़ की लागत से पुनर्विकसित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में रेलवे ट्रैक पर 1283 फ्लाईओवर और रोड अण्डर ब्रिज का निर्माण किया गया है। माननीय रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने मध्य प्रदेश में रेल परियोजनाओं को पर्याप्त बजट के माध्यम से लक्षित समय में पूरा करने की बात पर जोर दिया।

संरक्षा के बारे में बताते हुए माननीय रेलमंत्री ने कहा कि भारतीय रेलवे पर अत्यानुधिक कवच प्रणाली को विभिन्न रेलमार्गों पर स्थापित किये जाने सम्बन्धी कार्य तीव्र गति से किये जा रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश में 4591 रूट किलोमीटर रेलमार्ग पर कवच प्रणाली कार्य योजना तैयार कर ली गई है। उन्होने बताया कि कवच प्रणाली को स्थापित करने में आप्टिकल फाइबर केबल बिछाने, टावर लगाने, डेटा सेन्टर स्थापित करने और आरएफआईडी डिवाइस लगाने जैसे कार्य किए जाते है।

यात्री सुविधाओं के विषय में माननीय रेलमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में विभिन्न जिलों को कवर करते हुए 5 जोड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें एवं 4 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें संचालित की जा रही हैं। मध्य प्रदेश के लिए यह रेल बजट राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ-साथ यात्री सुविधाओं में भी वृद्धि होगी।

माननीय रेलमंत्री जी ने बताया कि माल ढुलाई और लॉजिस्टिक्स दक्षता की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए, केन्द्रीय बजट में पश्चिम बंगाल के डंकुनी से गुजरात के सूरत तक एक नए समर्पित मालवाहक कॉरिडोर का प्रस्ताव किया गया है, जो ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगा। 2,052 किमी लंबा यह कॉरिडोर मौजूदा पश्चिमी समर्पित मालवाहक कॉरिडोर से जुड़ेगा, जिससे पश्चिमी तट के बंदरगाहों तक माल की बिना किसी रुकावट के आवाजाही हो सकेगी। केन्द्रीय मंत्री श्री वैष्णव ने बताया कि यह पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में व्यापार प्रवाह को सुदृढ़ करेगा, मौजूदा रेल नेटवर्क पर दबाव कम करेगा और माल ढुलाई की दक्षता बढ़ाएगा, जिससे औद्योगिक विकास और आपूर्ति श्रृंखलाओं को काफी लाभ मिलेगा।

माननीय रेल मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान यह भी कहा कि उज्जैन में आगामी सिंहस्थ मेला को दृष्टिगत रखते हुए रेलवे द्वारा तैयारियाँ जोर-शोर से की जा रही हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि मेला अवधि के दौरान यात्रियों एवं श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी तथा रेल संचालन एवं यात्री सुविधाओं के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित किए जा रहे हैं। केन्द्रीय बजट 2026-27 में घोषित पहलों के साथ, भारतीय रेलवे 'विकसित भारत' के विजन के अनुरूप तेज कनेक्टिविटी, कुशल लॉजिस्टिक्स और सुदृढ़ अवसंरचना प्रदान करते हुए राष्ट्र निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए तैयार है।

इसके साथ ही माननीय रेलमंत्री ने बताया कि केन्द्रीय बजट 2026-27 में गुजरात राज्य को 17,366 करोड़ रुपये तथा राजस्थान राज्य को 10,288 करोड़ रुपये का रेल बजट आवंटन किया गया है। चूँकि पश्चिम रेलवे का रतलाम मंडल गुजरात एवं राजस्थान दोनों राज्यों को सीधे जोड़ता है, अतः इन दोनों राज्यों में रेल अवसंरचना, सेफ्टी एवं यात्री सुविधाओं पर होने वाले विकास कार्यों का प्रत्यक्ष लाभ रतलाम मंडल को भी मिलेगा। इससे रतलाम मंडल में रेल परियोजनाओं, परिचालन क्षमता तथा यात्री सुविधाओं के विकास को नई गति प्राप्त होगी।

केन्द्रीय बजट 2026-27 में घोषित पहलों के साथ, भारतीय रेलवे 'विकसित भारत' के विजन के अनुरूप तेज कनेक्टिविटी, कुशल लॉजिस्टिक्स और सुदृढ़ अवसंरचना प्रदान करते हुए राष्ट्र निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए तैयार है।

अनधिकृत पार्किंग से अग्निशमन व बचाव कार्य में बाधा आने पर वाहन मालिकों के विरुद्ध सीधे एफआईआर दर्ज की जाएगी

मुंबई के नागरिकों के जीवन की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी बृहन्मुंबई महानगरपालिका के मुंबई अग्निशमन दल के बचाव कार्यों में अनधिकृत वाहन पार्किंग के कारण बार-बार बाधाएँ उत्पन्न हो रही हैं। इस पृष्ठभूमि में, यदि किसी आग या आपदा स्थल पर त्वरित प्रतिक्रिया में अनधिकृत रूप से खड़े वाहनों के कारण बाधा आती है, तो संबंधित वाहन मालिकों के विरुद्ध सीधे पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की जाएगी।

इस संबंध में बृहन्मुंबई महानगरपालिका के आयुक्त एवं प्रशासक श्री भूषण गगराणी तथा अतिरिक्त आयुक्त (शहर) डॉ. (श्रीमती) अश्विनी जोशी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं। ये निर्देश आयुक्त कार्यालय में हुई चर्चा के बाद जारी किए गए हैं और नगर प्रशासन द्वारा इस बाबत आदेश भी निर्गत कर दिए गए हैं।

बृहन्मुंबई महानगरपालिका का मुंबई अग्निशमन विभाग आगजनी की घटनाओं तथा अन्य प्राकृतिक एवं मानव-निर्मित आपदाओं से नागरिकों, पशु-पक्षियों और संपत्ति की रक्षा के लिए जिम्मेदार है। अग्निशमन एवं बचाव कार्यों को प्रभावी ढंग से अंजाम देने हेतु विभाग सुसज्जित वाहनों, आधुनिक उपकरणों और प्रशिक्षित मानवबल के साथ त्वरित प्रतिक्रिया देकर घटना स्थल पर पहुँचता है।

हालाँकि, पिछले कुछ वर्षों से यह देखा गया है कि मुंबई महानगर में नागरिकों द्वारा सड़कों के किनारे विभिन्न प्रकार के वाहन अवैध रूप से पार्क किए जाते हैं। ऐसे वाहन त्वरित प्रतिक्रिया या वास्तविक दुर्घटना स्थल तक पहुँचने में बाधा उत्पन्न करते हैं, जिससे अग्निशमन एवं बचाव कार्यों को करने में गंभीर कठिनाइयाँ आती हैं और जीवन व संपत्ति की हानि में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। यह अत्यंत गंभीर विषय है।

महानगर के कई मार्गों पर नागरिकों द्वारा अवैध रूप से वाहन पार्क किए जाते हैं। आपदा की स्थिति में, इससे मुंबई अग्निशमन विभाग के वाहनों को समय पर घटनास्थल तक पहुँचने या तत्काल कार्रवाई करने में दिक्कतें आती हैं।

सम्पादकीय

क्या आर्थिक समीक्षा के सुझावों से कमजोर होगा 'सूचना का अधिकार' कानून?

सूचना का अधिकार (आरटीआइ) कानून ने देश में लोकतंत्र की नींव को और मजबूत किया है। इसका मुख्य उद्देश्य शासन के कामकाज में पारदर्शिता लाना और जवाबदेही तय करना है। यह देश के नागरिकों को अधिकार देता है कि वे सरकारी तंत्र और उसके कार्यों की जानकारी हासिल कर सकते हैं। यानी यह कानून सरकार और जनता के बीच सूचना के सेतु के रूप में काम करता है और परस्पर भरोसे का निर्माण करता है।

भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और दोषियों को कानून के कठघरे में लाने की प्रक्रिया में भी इसकी महती भूमिका है। स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए जरूरी इन विशेषताओं में अगर कमी या कटौती की जाती है, तो निश्चित तौर पर यह कानून कमजोर होगा। यह मसला इसलिए चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि संसद में हाल में पेश की गई आर्थिक समीक्षा रपट में आरटीआइ कानून का फिर से अध्ययन करने की वकालत की गई है।

तर्क दिए गए हैं कि इस कानून में कुछ ऐसे प्रावधान किए जाने की जरूरत महसूस की जा रही है, ताकि गोपनीय रपट और मसविदों को सार्वजनिक किए जाने से छूट प्राप्त की जा सके। गौरतलब है कि लंबे समय से सूचना के अधिकार की मांग के मद्देनजर वर्ष 2005 इससे संबंधित कानून को लागू किया गया था। इसके तहत देश का हर नागरिक सरकारी विभाग और संस्थाओं से उनके कामकाज, योजनाओं एवं उनके प्रभाव, वित्तीय स्थिति तथा नियमों आदि की जानकारी मांग सकता है।

संबंधित अधिकारी तय समय के भीतर यह सूचना उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होते हैं। मगर समय के साथ सरकारी तंत्र की उदासीनता, लापरवाही और निहित स्वार्थों के कारण जानकारी छिपाने के प्रयासों से इस कानून की प्रभावशीलता में कमी देखी गई है, जो चिंता का विषय है। ऐसे में आर्थिक समीक्षा रपट में सूचना के अधिकारों का फिर से अध्ययन करने और कुछ मामलों में छूट हासिल करने की वकालत ने चिंता के स्तर को और बढ़ा दिया है।

एक तरफ सरकार जब अपने कामकाज में 'पारदर्शिता लाने' और भ्रष्टाचार को लेकर 'कतई बर्दाश्त नहीं करने' की नीति अपनाने पर जोर देती हो और दूसरी तरफ सूचना के अधिकारों को सीमित करने का प्रयास किया जाए, तो यह नीति और नीयत के बीच विरोधाभास पैदा करता है। आर्थिक समीक्षा में यह भी उल्लेख किया गया है कि आरटीआइ अधिनियम का मकसद कभी भी इसे व्यर्थ की जिज्ञासा का जरिया बनाने का नहीं था, न ही इसका उद्देश्य बाहर बैठकर सरकार के हर छोटे-छोटे काम में दखल देना या उसे नियंत्रित करना था।

यह बात सही है कि बिना कारण या सरकार के कामकाज में किसी सुनियोजित तरीके से बाधा उत्पन्न करने के लिए इस कानून का सहारा लेना उचित नहीं है। मगर सवाल यह है कि इस तरह आरटीआइ कानून का दुरुपयोग करने वालों की तादाद कितनी होगी? जाहिर है, इसमें कुछ खास वर्ग के चंद लोग ही शामिल होंगे, पर क्या उन पर अंकुश लगाने के लिए सभी नागरिकों के सूचना के अधिकार को सीमित किया जाना चाहिए?

इस कानून में पहले से ऐसे कई प्रावधान मौजूद हैं, जिनके तहत राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता, जांच प्रक्रिया और व्यक्तिगत गोपनीयता समेत अन्य संवेदनशील मसलों की जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती। अब अगर सूचना को रोकने के और प्रावधान किए जाते हैं, तो इससे यह कानून वास्तव में कमजोर होगा और इसका मकसद भी अधूरा ही रह जाएगा।

भारत-यूरोपीय संघ समझौता- यूरोप की नई दोस्ती से अमेरिका को कैसे लगा रणनीतिक झटका

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह वाक्य- 'भारत-यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता सभी सौदों की जननी है', सोशल मीडिया पर खूब प्रसारित हुआ है। 'जननी जन्म भूमिश्च' को गति देने वाले यूरोप के दो ताकतवर देश हैं- ब्रिटेन और जर्मनी। इस बहुचर्चित श्लोक का पहला वाक्य है, 'मित्राणि धन धान्यानि प्रजानां सम्मतानिव।' अर्थात, 'मित्र, धन-धान्य आदि का संसार में बहुत अधिक सम्मान है।' ब्रिटेन और जर्मनी ने जो कुछ किया, उससे अमेरिका तिलमिलाया हुआ है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते से पहले ब्रिटेन और भारत ने जुलाई 2025 में मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के बाद ब्रिटेन का यह सबसे बड़ा व्यापार समझौता था। भारत और यूरोपीय देशों की इस साझेदारी से अमेरिकी शुल्क नीति के प्रभाव को कम करने में खासी मदद मिलेगी।

ठीक इसी तरह के अभियान के तहत ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किअर स्टारमर हाल ही में आधिकारिक दौरे पर बेजिंग पहुंचे। उनके साथ करीब साठ सदस्यों का व्यापार एवं सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद रहा। स्टारमर का दौरा इस महीने कई पश्चिमी नेताओं के चीन दौरे के बाद हुआ। स्टारमर की यह यात्रा निश्चित रूप से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को असहज करने वाली है। इस दौरान स्टारमर ने कहा कि चीन के साथ ब्रिटेन के रिश्तों को और बेहतर बनाना जरूरी है। आठ साल में किसी ब्रिटिश नेता का यह पहला चीन दौरा है।

इस वर्ष चार जनवरी को आयरिश प्रधानमंत्री मिशेल मार्टिन ने चीन का दौरा किया था, 25 जनवरी को फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओर्पो बेजिंग पहुंचे थे। फ्रांस

के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और स्पेन के राजा फेलिप षष्टम ने पिछले साल के आखिर में चीन का दौरा किया था। माना जा रहा है कि जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज फरवरी में चीन का दौरा कर सकते हैं।

भारत-यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को लेकर चीन को कोई परेशानी महसूस नहीं हो रही है। इस मामले में उसे भारत इसलिए प्रतिस्पर्धी नहीं लग रहा, क्योंकि चीन भी अमेरिका का सताया हुआ है। सवाल है कि ट्रंप की नीतियों से असहज यूरोपीय शासन प्रमुखों के चीन दौरों से क्या मायने निकलते हैं? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर ने बेजिंग दौरे के दौरान एक कार्यक्रम में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से कहा, 'चीन दुनिया का एक महत्त्वपूर्ण राष्ट्र है और यह जरूरी है कि हम और ज्यादा बेहतर रिश्ते बनाएं।' इस पर जिनपिंग ने भी स्पष्ट किया कि वे स्थिर और व्यापक रणनीतिक साझेदारी विकसित करने को तैयार हैं।

स्टारमर ने जिनपिंग के साथ अपनी मुलाकात को वास्तविक परिणामों के साथ बहुत अच्छी एवं रचनात्मक बैठक बताया और चीन में ब्रिटिश व्यवसायों के लिए बेहतर अवसरों पर जोर दिया। दोनों पक्षों ने मीडिया को संकेत दिया कि शराब की विशेष किस्म पर चीन के शुल्क कम करने और चीन के लिए वीजा-मुक्त यात्रा के मुद्दे पर अच्छी प्रगति हुई है।

अब सवाल यह है कि स्टारमर की इस यात्रा के बाद क्या चीन और यूरोपीय संघ के बीच 'कांप्रिहेंसिव एग्रीमेंट आन इन्वेस्टमेंट' (सीएआइ) को गति मिलेगी? हालांकि, चीन ने बातचीत फिर से शुरू करने और आर्थिक संबंधों को गहरा करने में दिलचस्पी दिखाई है। स्टारमर का यह दौरा वर्ष 2025 के आर्थिक और वित्तीय संवाद (ईएफडी) के बाद हुआ, जिसके बारे में ब्रिटेन के व्यापार और व्यवसाय विभाग ने दावा किया है कि इससे 600 मिलियन पाउंड का तत्काल लाभ हुआ है एवं वर्ष 2018 के बाद पहली बार ब्रिटेन-चीन संयुक्त आर्थिक और व्यापार आयोग (जेटको) की स्थापना हुई है।

दरअसल, भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता होने से पहले ही इसके स्पष्ट संकेत मिलने से उत्साहित होकर ट्रंप विरोधी ताकतें एकजुट होने लगीं। इस महीने की शुरुआत में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने बेजिंग का दौरा किया था। यह घोषणा करने के बाद कि कनाडा कुछ चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों पर शुल्क कम करेगा, ट्रंप ने धमकी दी कि अगर चीन के साथ कनाडा कोई व्यापार समझौता करता है, तो वह कनाडा से आयात पर सौ फीसद शुल्क लगा देंगे।

अब कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ब्रिटेन के अपने समकक्ष स्टारमर की बेजिंग यात्रा से मजबूती महसूस कर रहे हैं। यह यात्रा ऐसे समय में हुई, जब यूरोपीय देश चीन के 1.2 ट्रिलियन डालर के वैश्विक व्यापार अधिशेष से चिंतित हैं। यूरोपीय नेताओं को लगता है कि सस्ता चीनी सामान उनके घरेलू उद्योगों को खोखला कर रहा है। मगर ट्रंप की वजह से इस कड़वे घूंट को भी यूरोपीय नेता मीठा-मीठा मानने लगे हैं।

किअर स्टारमर के दौरे के बारे में पूछे जाने पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि यह दोनों देशों के साझा हितों के मद्देनजर महत्त्वपूर्ण है और इससे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के दो स्थायी सदस्यों के तौर पर चीन और ब्रिटेन के लिए वैश्विक शांति, स्थिरता और विकास में मदद मिलेगी।

सुरक्षा परिषद में पांच स्थायी सदस्य हैं- चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। वर्तमान परिदृश्य में इनमें से तीन ब्रिटेन, रूस और चीन एक तरफ दिखते हैं। ऐसे में यदि वीटो के उपयोग का विकल्प न हो, तो अमेरिका अलग-थलग पड़ सकता है। मगर यह समझना जरूरी है कि दवा का कुछ नकारात्मक प्रभाव भी होता है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारतीय कार निर्माताओं के शेयरों में पांच फीसद तक की बड़ी गिरावट देखी गई।

इस समझौते से यूरोपीय कंपनियों को सीधा फायदा होने की संभावना जताई जा रही है। माना जा रहा है कि इससे मशीनरी, आप्टिकल, मेडिकल, सर्जिकल और इलेक्ट्रिकल उपकरणों जैसे यूरोपीय उत्पादों की भारतीय बाजारों में आवक बढ़ेगी। एक सबसे अहम बात यह है कि यूरोप की कई कंपनियों की निर्माण इकाइयां चीन में लगी हैं। ऐसे में नाम भले यूरोपीय संघ का हो, मगर उत्पाद चीन से ही आएगा। शायद इसलिए भी चीन इस समझौते से असहज नहीं है।

दूसरी ओर, ट्रंप प्रशासन इस बात से निराश है कि नवंबर के मध्यावधि चुनावों से पहले प्रस्तावित समझौते तेजी से पूरे नहीं हो पा रहे हैं। भारत-ईयू व्यापार समझौते से अमेरिका को जोर का झटका धीरे से लगा है। अटलांटिक पारीय संधि खतरे में है। अमेरिका के वित्त मंत्री का कहना है कि इस समझौते से यूरोपीय संघ ने यूक्रेन से पहले व्यापार को प्राथमिकता दी है। ट्रंप की दबावकारी नीतियों के कारण अमेरिका वैश्विक मंच पर धीरे-धीरे अलग-थलग पड़ रहा है। न्यूटन के तीसरे नियम की तरह–हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया हो रही है।

अकिंचन होना दरिद्रता नहीं, परम वैभव की प्राप्ति है

हमारे अस्तित्व का समस्त ताना-बाना आगमन और प्रस्थान के दो ध्रुवों के बीच झूलता एक स्पंदन है। शून्य से निकलकर शून्य की ओर बढ़ते इन कदमों के बीच जो कुछ घटित हो रहा है, बस वही जीवन की पूर्णता है। जब चेतना इस सत्य को आत्मसात कर लेती है कि यहां कुछ भी मुट्ठी में भींचकर रखने योग्य नहीं है, वहीं से असीमित निर्भयता का जन्म होता है, जहां अभाव भी स्वभाव एवं उत्सव बन जाता है। यह किसी सांसारिक रिक्तता का नाम नहीं, बल्कि मोह के विसर्जन से उपजी एक आंतरिक संपन्नता है।

हम जिस अकिंचनता के साथ इस संसार की देहरी पर कदम रखते हैं, वही निर्भार स्थिति हमारे प्रस्थान का भी शाश्वत सत्य है। मनुष्य का अहंकार उसे संग्रह के लिए प्रेरित करता है, पर आत्मा सदैव विसर्जन में ही शांति पाती है।

अक्सर मनुष्य अपने चारों ओर दीवारों का एक मायाजाल बुनता है। वह ईंटों, पत्थरों और कंक्रीट से एक सुरक्षा कवच तैयार करता है, जिसे वह 'और' की संज्ञा देता है। मगर एकांत के क्षणों में यह सत्य उभरकर आता है कि ये घर केवल शरीर को शरण दे सकते हैं, चेतना को नहीं, क्योंकि शरीर तो खुद एक अस्थायी डेरा है।

वैभव के उत्तुंग शिखरों पर विराजमान रहने वाले लोग भी अक्सर एक भयावह सूनेपन के साये में जीते हैं। यह वीराना बाहर का नहीं, बल्कि अंतर्जगत की मरुभूमि है। जब तक हृदय के भीतर संवेदनाओं का मधुर संगीत नहीं गूंजता, तब तक स्वर्ण-जड़ित प्रासाद भी एक निस्तब्ध मरघट की भांति ही प्रतीत होते हैं।

मनुष्य का वास्तविक निवास वह नहीं, जहां वह शरीर से उपस्थित है, बल्कि वह है जहां उसका मन विश्राम पाता है। बाहर की दुनिया में जिसे हम साम्राज्य विस्तार कहते हैं, वह अक्सर हमारे भीतर की संकीर्णता को ढकने का एक निष्फल प्रयास मात्र होता है। विशाल भवनों की छाया में अक्सर लघु हृदय सिसकते देखे जा सकते हैं।

इस जगत के रंगमंच पर जिसे 'धन' मानकर पूजा जाता है, वह वास्तव में एक अदृश्य बोझ है, जिसे हम सुरक्षा के नाम पर ढोते रहते हैं। स्वर्ण और रजत की चमक केवल उन आंखों को सम्मोहित करती है, जो यथार्थ की ज्योति से अपरिचित हैं। वास्तविक संपदा तो वह है जो हृदय की उर्वर भूमि से उपजती है- वह निस्वार्थ अनुराग, जो किसी सौदेबाजी का मोहताज नहीं।

व्यापार तो केवल वस्तुओं और मुद्राओं का होता है, आत्माओं का विनिमय तो केवल प्रेम की भाषा में संभव है। जहां लाभ और हानि के तराजू पर हर संबंध को तौला जाने लगे, वहां जीवन का नैसर्गिक छंद मौन हो जाता है। अपनी मंजिल केवल भौतिक संचय को मान लेने वाले लोग उस मृगतृष्णा के पीछे अंतहीन दौड़ लगाते हैं, जो कभी तृप्ति का एक घूंट भी प्रदान नहीं करती।

इसके विपरीत, एक जागृत मन के लिए सफलता और विफलता का मूल्य भोर की उस ओस जैसा है, जो सूर्य की पहली रश्मि के स्पर्श के साथ ही शून्य में विलीन हो जाती है। संचय की इस अंधी दौड़ में हम अक्सर उसे खो देते हैं, जिसे पाने के लिए हमने यह सब संजोया था। प्रकृति के खुले विस्तार में बिना किसी कृत्रिम छत या सुरक्षा के जीना, समय के प्रवाह के साथ पूरी तरह एकाकार होना है। जब मनुष्य अपनी सीमाओं का विसर्जन कर देता है, तो यह संपूर्ण ब्रह्मांड ही उसका अपना आंगन बन जाता है।

मर्यादाओं के तट और भावनाओं के घाट अलग-अलग होकर भी एक ही धारा के दो छोर हैं। एक पक्ष जहां संयम की कठोरता का बोध कराता है, वहीं दूसरा पक्ष समर्पण और कोमलता के माधुर्य का। एक सच्चा पथिक वही है, जो इन दोनों तटों के बीच समभाव से बहना जानता हो। उसके लिए आकाश से गिरती बूंदें कोई विपदा नहीं, बल्कि अस्तित्व का मधुर अभिषेक हैं। वह अपनी असुरक्षा की चरम अवस्था में ही सबसे अधिक अभेद्य अनुभव करता है, क्योंकि उसने 'स्वयं' को बचाने की व्याकुलता त्याग दी है। असुरक्षा का भय तभी तक है, जब तक कुछ खोने का डर है। जिसके पास खोने को कुछ शेष नहीं, वह सम्राट है।

समय एक ऐसा निर्मम प्रवाह है जो निरंतर पुराने को मिटाता और नए का सृजन करता चलता है। यहां कुछ भी अचल नहीं है- न हमारी पीड़ा के कांटे और न ही सुखों के पुष्प। लाभ और हानि की चिंता में वे घुलकर रीते होते रहते हैं, जिन्होंने समय को केवल अपनी आयु के खंडों में देखा है। मगर जिसने समय की अखंडता को पहचान लिया है, उसके लिए संसार का हर उतार-चढ़ाव एक क्रीड़ा मात्र है। जैसे पतझड़ के बाद वसंत का आगमन एक शाश्वत चक्र है, वैसे ही अभाव के बाद भाव और मृत्यु के बाद नूतन सृजन की प्रक्रिया चलती रहती है। इस चक्र में वही शांत रह सकता है, जो इसके केंद्र में स्थित है। और वह केंद्र अनासक्ति का बिंदु है।

यह समस्त वैचारिक यात्रा अंततः हमें एक ऐसे शिखर पर खड़ा कर देती है, जहां से जगत की जटिल गुत्थियां अत्यंत सरल और तुच्छ दिखाई देने लगती हैं। इस धरती पर मनुष्य एक अतिथि के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, और एक विवेकशील अतिथि कभी सराय के सामान से अपना मोह नहीं जोड़ता।

मानवीय सार्थकता इस संचय में नहीं कि मुट्ठियों में क्या बंद रहा, बल्कि इसमें है कि प्रस्थान के क्षण कितने सहज और भारमुक्त रहे। जिस क्षण 'ममत्व' के संकुचित घेरे टूटते हैं और व्यक्ति समष्टि के भाव में स्थित होता है, उसी क्षण वह वास्तव में चैतन्य होता है। यही वह स्थिति है जहां व्यक्ति भीड़ में रहकर भी अपनी निजता के एकांत में प्रसन्न रहता है और अभावों के बीच रहकर भी अपनी पूर्णता का उत्सव मनाता है। अकिंचन होना दरिद्रता नहीं, बल्कि उस परम वैभव की प्राप्ति है, जहां इच्छाएं शांत हो जाती हैं और केवल कृतज्ञता शेष रह जाती है। यही जीवन का अंतिम सत्य और परम उत्सव है।

पक्षियों के कलरव पर मंडरा रहा है ध्वनि प्रदूषण का 'अदृश्य' खतरा

आज शहरीकरण और तकनीकी विकास की दौड़ में तेज गति से आगे बढ़ती दुनिया में ध्वनि प्रदूषण की समस्या भी गंभीर होती जा रही है। यह प्रदूषण का एक ऐसा स्वरूप है, जिसके प्रभाव को अक्सर कम आंका जाता है। वायु और जल प्रदूषण के विपरीत, ध्वनि प्रदूषण दिखाई नहीं देता। यह कोई ठोस अवशेष नहीं छोड़ता, लेकिन इसका प्रभाव गहरा और दूरगामी होता है, जो धीरे-धीरे पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवेश कर उसे असंतुलित कर देता है।

इस बढ़ते खतरे से सबसे अधिक पक्षी प्रभावित हो रहे हैं, जिनका संपूर्ण जीवन ही ध्वनि पर आधारित है। पक्षियों के लिए ध्वनि केवल परिवेश की एक पृष्ठभूमि भर नहीं है, बल्कि उनके अस्तित्व, संचार, प्रजनन और दिशा-निर्धारण का मूल आधार है। जैसे-जैसे शहरों में शोर बढ़ रहा है और मानवीय गतिविधियां पर्यावरण के विपरीत होती जा रही हैं, वैसे-वैसे वह प्राकृतिक वातावरण भी नष्ट होता जा रहा है, जिस पर पक्षियों का जीवन टिका हुआ है।

यही कारण है कि पक्षियों की अनेक प्रजातियां लुप्त हो गई हैं और कई विलुप्ति की कगार पर पहुंच गई हैं। पक्षी आपस में संवाद के लिए ध्वनि पर निर्भर रहते हैं। उनके गीत मात्र मधुर स्वर नहीं होते, बल्कि ध्वनिक संकेत होते हैं, जिनका उपयोग वे अपने क्षेत्र की पहचान करने, साथी को आकर्षित करने, शिकारियों से सावधान करने और सामाजिक संबंध बनाए रखने के लिए करते हैं।

प्रत्येक पक्षी प्रजाति ने अपने प्राकृतिक आवास के अनुरूप एक विशिष्ट ध्वनि-सीमा और शैली विकसित की है। मगर जब यातायात, निर्माण कार्य, औद्योगिक मशीनें, हवाई जहाज और शहरी भीड़-भाड़ से मानवीय शोर इन ध्वनि सीमाओं पर हावी हो जाता है, तो पक्षियों की आवाज दब जाती है या पूरी तरह गुम हो जाती है। इससे उनका संवाद बाधित हो जाता है। जब किसी पक्षी का संकेत अपने उद्देश्य तक नहीं पहुंच पाता, तो इसका प्रभाव क्षणिक नहीं होता, बल्कि उसके पूरे जीवन-चक्र को प्रभावित करता है।

ध्वनि प्रदूषण का सबसे गंभीर प्रभाव पक्षियों के प्रजनन और जोड़ी बनाने की प्रक्रिया पर पड़ता है। अनेक पक्षी प्रजातियां साथी के चयन में गीत की गुणवत्ता, स्वर की ऊंचाई और निरंतरता को महत्त्वपूर्ण मानती हैं। मादा पक्षी प्रायः उसी नर को चुनती हैं, जिसका गीत अधिक स्पष्ट और शक्तिशाली होता है, क्योंकि यह उसके अच्छे स्वास्थ्य और श्रेष्ठ आनुवंशिक गुणों का संकेत माना जाता है।

शोरगुल वाले वातावरण में नर पक्षियों को अपने गीत में बदलाव करने के लिए विवश होना पड़ता है। वे या तो स्वर को ऊंचा कर लेते हैं या फिर गीत की अवधि को छोटा कर देते हैं। ये बदलाव शोर के बीच गीत सुनाई देने में सहायक हो सकते हैं, लेकिन इससे मधुरता और प्रभावशीलता कम हो जाती है। लंबे समय में इसका परिणाम यह होता है कि जोड़ों की संख्या घटती जाती है। अंडों की संख्या कम होती है और उनसे बच्चों के निकलने की दर भी घटती जाती है। अंततः पक्षियों की आबादी में निरंतर गिरावट आने लगती है।

ध्वनि प्रदूषण शिकारी को पहचानने और खतरे का आभास करने की पक्षियों की क्षमता को भी गंभीर रूप से प्रभावित करता है। प्राकृतिक आवासों में पत्तियों की सरसराहट, अन्य पक्षियों की चेतावनी, पुकार या हल्की आहट संभावित खतरे का संकेत देती हैं। मगर निरंतर पृष्ठभूमि का शोर इन संकेतों को ढक देता है, जिससे पक्षी समय रहते खतरे को नहीं पहचान पाते।

निरंतर इस खतरे के कारण पक्षी हमेशा सतर्क रहते हैं। इससे उनमें तनाव का स्तर बढ़ जाता है। दीर्घकालिक तनाव उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है और उनकी जीवन अवधि को भी घटाता है। इस प्रकार ध्वनि प्रदूषण अप्रत्यक्ष रूप से भी पक्षियों की संख्या में गिरावट का कारण बनता है।

पक्षियों के जीवन का एक और महत्त्वपूर्ण पक्ष प्रवासन भी ध्वनि प्रदूषण से गंभीर रूप से प्रभावित होता है। अनेक प्रवासी पक्षी अपनी लंबी यात्राओं के दौरान ध्वनिक संकेतों और पर्यावरणीय ध्वनियों पर निर्भर रहते हैं। कृत्रिम शोर उनके दिशा-बोध को भ्रमित करता है, जिससे वे अपने मार्ग से भटक जाते हैं या सही दिशा में लौटने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा खर्च करने पर मजबूर होते हैं।

शहरी शोर और कृत्रिम रोशनी का प्रभाव अक्सर प्रवासी पक्षियों पर पड़ता है। वे कई बार इमारतों से टकरा जाते हैं या अत्यधिक थकावट महसूस करते हैं या फिर भोजन की कमी से मर जाते हैं। शहरी वातावरण भी पक्षियों के लिए चुनौती है। कुछ पक्षी प्रजातियां आश्चर्यजनक रूप से अनुकूलन क्षमता दिखाते हुए शहरों में जीवित रह जाती हैं, मगर इस अनुकूलन की भी एक कीमत होती है। इसके अलावा सभी प्रजातियां समान रूप से अनुकूलन नहीं कर पातीं।

वन क्षेत्रों में रहने वाले और विशिष्ट आवासों पर निर्भर या सीमित स्वर सीमा वाले पक्षी शहरी शोर सहन नहीं कर पाते। नतीजा यह कि कुछ ही शोर-सहिष्णु प्रजातियां बची रहती हैं। पक्षियों की घटती आबादी के पारिस्थितिक परिणाम अत्यंत गहरे और व्यापक होते हैं। पक्षी पारिस्थितिकी तंत्र में परागण, बीज प्रसार, कीट नियंत्रण और मृत जीवों की सफाई में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब पक्षियों की संख्या कम होती है, तो कीटों की आबादी अनियंत्रित रूप से बढ़ जाती है।

खाद्य शृंखलाएं असंतुलित हो जाती हैं। इस प्रकार ध्वनि प्रदूषण केवल पक्षियों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र और अंततः मानव कल्याण के लिए एक गंभीर खतरा बन जाता है। समस्या गंभीर होने के बावजूद, ध्वनि प्रदूषण पर अन्य पर्यावरणीय खतरों की तुलना में अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया जाता है। वायु और जल प्रदूषण के लिए जहां स्पष्ट मानक और नियम बनाए गए हैं, वहीं ध्वनि प्रदूषण संबंधी नियम प्रायः अपूर्ण या प्रभावहीन रहते हैं।

शहरी नियोजन में ध्वनिक पारिस्थितिकी पर बहुत कम विचार किया जाता है और विकास परियोजनाओं में पर्यावरणीय संतुलन की अपेक्षा आर्थिक लाभ को प्राथमिकता दी जाती है। असंख्य छोटे-छोटे शोर स्रोत मिल कर ऐसा वातावरण तैयार कर देते हैं, जो वन्यजीवों के लिए अत्यंत प्रतिकूल होता है, लेकिन इसे आधुनिक जीवन का अनिवार्य हिस्सा मान लिया गया है। पक्षियों पर ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है।

वर्तमान समय में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जागरूकता बेहद जरूरी है। शोर को अक्सर एक छोटी असुविधा मान कर अनदेखा किया जाता है। यदि लोगों को यह समझाया जाए कि शोर का पारिस्थितिकी पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है, तो वे अधिक जिम्मेदारी निभा सकते हैं। अनावश्यक 'हार्न' बजाने से बचना, तेज आवाज वाले मनोरंजन को सीमित करना और वन्यजीव-अनुकूल नीतियों का समर्थन करना, इस दिशा में छोटे, लेकिन अहम कदम हो सकते हैं। सामुदायिक निगरानी कार्यक्रम भी ध्वनि प्रदूषण को समझने और नियंत्रित करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं।

जैसे-जैसे मानव समाज अधिक शोरगुल वाला होता जा रहा है, वैसे-वैसे पक्षियों की प्राकृतिक ध्वनियां मौन में बदलती जा रही हैं। पक्षियों को ध्वनि प्रदूषण से बचाना केवल संरक्षण का कार्य नहीं, बल्कि प्रकृति के नाजुक संतुलन को बनाए रखने की हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, ताकि आने वाली पीढ़ियां एक ऐसी दुनिया में जीवन बिताएं, जहां पक्षियों का कलरव गूंजता हो।

किन्नर अखाड़ा की प्रदेश अध्यक्ष के विशाल भण्डारा में श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया प्रसाद

तीर्थराज में अन्नदान से अक्षय पुण्य की प्राप्ति : कल्याणीनंद गिरि

माघ मेला से लौटते श्रद्धालुओं ने चार स्थानों पर चल रहे भण्डारे में लिया प्रसाद

प्रयागराज। किन्नर अखाड़ा की प्रदेश अध्यक्ष महामण्डलेश्वर स्वामी कल्याणीनंद गिरि महराज (छोटी मां) के नेतृत्व में आज मेला क्षेत्र के चार स्थानों पर विशाल भण्डारा चलाया गया जिसमें अपने घरों को लौट रहे श्रद्धालुओं ने परिवार सहित प्रसाद लिया। बडी संख्या में किन्नर संत और शिष्य माघ मेला के सेक्टर-6 ओल्ड जीटी, संगम लोवर में लगे किन्नर अखाड़ा एवं नागवासुकी मार्ग - हर्षवर्धन मार्ग पर लगे अखिल भारतीय कल्याणी सनातन सेवा ट्रस्ट की ओर से विशाल भण्डारा चलाया गया जिसमें बडी संख्या में घर वापसी करते श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। श्रद्धालुओं को पूडी, कचौडी, सब्जी, रायता, बूंदी

और रसगुल्ले खिलाएं गये। किन्नर अखाड़ा की प्रदेश अध्यक्ष महामण्डलेश्वर स्वामी कल्याणीनंद गिरि (छोटी मां) महराज ने बताया कि इस दौरान बडी संख्या में किन्नर संत भण्डारा चलाने में लगे हुए थे जो श्रद्धालुओं को प्रेमपूर्वक खाना खिला रहे थे। उन्होने बताया कि माघ मास में कल्पवास करते हुए अन्नदान से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। श्रद्धालुओं के प्रसाद वितरण में किन्नर अखाडा की श्रीमहंत सरस्वतीनंद गिरि मुरादाबादी और कामाक्षी नंद गिरि, शुभम नंद गिरि, हर्षिता नंद गिरि, मनीषा नंद गिरि, शिवानी नंद गिरि, आलिया नंद गिरि सहित अन्य प्रमुख शिष्यों ने श्रद्धालुओं को खाना खिलाने में मदद किया। उन्होने बताया कि माघ मेला के दौरान प्रयागराज, यूपी, उडीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड सहित अन्य प्रदेशों के किन्नर संत और बडी संख्या में शिष्य माघी पूर्णिमा स्नान के बाद अपने आश्रम, घरों के लिए आज रवाना हो गये है। किन्नर अखाड़ा की प्रदेश अध्यक्ष महामण्डलेश्वर स्वामी कल्याणीनंद गिरि महराज (छोटी मां) ने बताया कि माघ मेले के छठवें एवं अंतिम स्नान पर्व महाशिवरात्रि 15 फरवरी का भी स्नान किन्नर अखाड़ा के संत, शिष्य संगम पर सुबह आठ बजे से करेगा।

त्रिवेणी तट पर बही सुरों की बयार, रंगारंग प्रस्तुतियों ने दर्शकों को किया मंत्रमुग्ध

प्रयागराज। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार एवं संस्कार भारती के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 'चलो मन गंगा-यमुना तीर' कार्यक्रम के अंतर्गत सोमवार को त्रिवेणी तट पर लोकगायन, नृत्य और भक्तिरस की अद्भुत छटा देखने को मिली। विविध सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने उपस्थित दर्शकों को भाव-विभोर कर दिया।

कार्यक्रम की शुरुआत अंकिता चतुर्वेदी की सुमधुर गायन प्रस्तुति से हुई। उन्होंने 'सब तीर्थ का राजा जग में पावन प्रयागराज है', 'मेरे भोले नाथ जी', 'मेरे नाम से पहले सियाराम लिख देना', 'मृगनयनी को यार', 'नवल रसिया' तथा सूफी गीत 'दमा दम मस्त कलंदर' प्रस्तुत कर वातावरण को भक्तिमय और संगीतमय बना दिया।

इसके उपरांत मीना खन्ना एवं उनके दल ने लोकनृत्यों की श्रृंखला प्रस्तुत की। 'हरि भरी धरती मा लहर लेहरवा मोरा' पर कजरी नृत्य, 'बारे भाग्य से आए श्रीराम' एवं 'प्रयाग में उतारे ढेड़िया' गीत पर ढेड़िया लोकनृत्य, 'परम प्रेममय राधिका, कृष्ण परम उल्लास' पर रासलीला तथा महिषासुर वध पर आधारित लोकनृत्य ने दर्शकों से खूब तालियाँ बटोरीं।

महाराष्ट्र से आए विशाल गेंदले एवं उनके साथी कलाकारों ने वाद्य यंत्र बैंड की प्रभावशाली प्रस्तुति दी। राग हंसध्वनि और राग यमन की शास्त्रीय जुगलबंदी

के साथ भजन 'ॐ जय जगदीश हरे', 'श्रीराम चंद्र कृपालु भजमन', 'रघुपति राघव राजा राम' एवं 'अच्युतम् केशवम्' की प्रस्तुति ने श्रोताओं को आध्यात्मिक आनंद से भर दिया।

कार्यक्रम के अंतिम चरण में जबावी बिरहा की प्रस्तुति में दिलीप कुमार यादव, संतोष चंचल, गोविन्द पाल, अर्चना, यशपाल, सत्यप्रकाश पटेल, ममता पटेल एवं यज्ञ नारायण ने बिरहा के माध्यम से लोकजीवन की संवेदनाओं को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया।

उपनिदेशक डॉक्टर आदित्य श्रीवास्तव, उपनिदेशक कार्यक्रम डॉक्टर मुकेश उपाध्याय व विभव मिश्रा, महामंत्री संस्कार भारती द्वारा सभी कलाकारों को पौधा देकर सम्मानित किया।

ओम नमः शिवाय के भण्डारे में तीन करोड श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया प्रसाद

बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, मेला क्षेत्र में तीन दर्जन गाडियों से खिलाया गया खाना

प्रयागराज। ओम नमः शिवाय प्रयागराज की ओर से माघ मेला के शुरू होने से विशाल भण्डारा चल रहा था, जो मेला के दौरान दो दर्जन स्थानों पर दिन, रात चलाया गया। इस दौरान लाखों कर्मचारी, श्रद्धालु और स्नानार्थियों ने भण्डारे में प्रसाद लिया। मेला क्षेत्र में चल रहे भण्डारे माघी पूर्णिमा रविवार से अब बंद हो गये है जबकि ओम नमः शिवाय प्रयागराज की ओर से अभी भी दिन, रात भण्डारा चल रहा है जहा बडी संख्या मे श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण कर रहे है।

माघ मेला मे सबसे बडा भण्डारा 49 वर्ष से ओम नमः शिवाय प्रयागराज का चल रहा है। इस बार भण्डारा नवंबर - 2025 से दिन, रात परेड की लाल सडक पर चल रहा है। माघ मेला के पहले स्नान पर्व पौष पूर्णिमा तीन जनवरी से अन्न क्षेत्र जो दर्जन भर स्थानों पर दिन, रात चल रहा था जहां लाखों लोग प्रतिदिन भण्डारे में खाना खा रहे थे। ओम नमः शिवाय भण्डारा के व्यवस्थापक शिवम सिंह ने बताया कि भण्डारे मे प्रतिदिन और रात श्रद्धालुओं की बहुत अधिक भीड हो रही है, संभावना है कि अभी तक तीन करोड से अधिक श्रद्धालुओं ने दो दर्जन स्थानों पर चल रहे विशाल भण्डारे में प्रसाद प्रसाद ग्रहण किया है।

ओम नमः शिवाय भण्डारा के व्यवस्थापक शिवम सिंह ने बताया कि माघ मेला के दौरान 38 डीसीएम आलू, 15 ट्क आटा, 25 ट्क चावल, पांच ट्क बेसन, 45 डीसीएम सब्जी, 50 कुंतल मसाला, पांच हजार किलो दही, 5000 लीटर दूध सहित अन्य खाध सामाग्रियों का प्रयोग भण्डारे में किया गया। उन्होने बताया कि 480 ट्रैक्टर लकडी और गैस का प्रयोग खाना बनाने मे किया गया। ओम नमः शिवाय भण्डारा के व्यवस्थापक शिवम सिंह ने बताया माघ मेला के दौरान परेड की लाल रोड, त्रिवेणी मार्ग, दारागंज के गल्ला मण्डी और संगम लोवर चौराहे पर भण्डारे का खाना बनता था जबकि 20 बैटरी वाले रिक्शे सहित अन्य दर्जन भर गाडियों से भण्डारे का खाना मेला क्षेत्र, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, लल्लू जी एण्ड संस, मेला कार्यालय, पुलिस सहित अन्य विभाग के लोगों को खाना खिलाया।

ओम नमः शिवाय के पूज्य गुरुदेव ने बताया कि जीवन का एक ही लक्ष्य है कि अन्न से मानव की सेवा करता रहूंगा जिससे कि कोई भूखा ना रहे। उन्होंने कहा कि संस्था का 50 वां स्थापना दिवस जनवरी 2027 में धूमधाम से मनाया जाएगा। बताया कि संस्था की ओर से अयोध्या धाम, कानपुर, लखनऊ और सीतापुर में विशाल भण्डारा चल रहा है जबकि इन सभी जिलों के मेडिकल कालेज और विवि के छात्रों को दोनों पालियों मे खाना खिलाया जा रहा है। कोविड के दौरान दोनों बार प्रयागराज, अयोध्या धाम, कानपुर, लखनऊ और सीतापुर में लाखो लोगो को वर्ष भर दिन, रात खाना खिलाया गया।

सनातन धर्म की सेवा, प्रचार-प्रसार जीवन का अंतिम उददेश्यः स्वामी हरि नारायण

छत्रपति शिवाजी के 13वीं पीढ़ी के राजगुरु स्वामी हरि नारायण ने माघ मास में श्रद्धालुओं के लिए चलाया विशाल भण्डारा

प्रयागराज। सिद्धेश्वर पुरुषार्थ दंडी स्वामी बालक आश्रम माघ मेला क्षेत्र प्रयागराज के स्वामी हरि नारायण समदर्शी के नेतृत्व में आज माघी पूर्णिमा के अवसर पर नारायण स्वरूप ने दण्डी स्वामियों, संन्यासियों को भण्डारे का प्रसाद खिलाकर अंगवस्त्र अचला प्रदान किया।

भगवती उपासक स्वामी हरि नारायण समदर्शी जी सिद्धेश्वर पुरुषार्थ दंडी स्वामी बालक आश्रम अध्यक्ष चित्रकूट अरैल प्रयागराज आराध्य तपोस्थली आश्रम पुणे महाराष्ट्र है। स्वामी हरिनारायण समदर्शी ने बताया कि प्रभु पद तो मेरा एक अच्छा पद है। छत्रपति शिवाजी महाराज के 13वीं पीढ़ी के वंशज के राजमाता छत्रपति कल्पना राजे भोसले को मैंने गुरु दीक्षा दिया है जो महाराष्ट्र में छत्रपति परिवार अभी भी है उनके वंशज राजा हैं सतारा महाराष्ट्र से लोकसभा सांसद हैं उनकी राजमाता ने मुझसे गुरु दीक्षा प्राप्त किया है। स्वामी हरिनारायण जी महराज ने बताया कि सनातन धर्म की सेवा, प्रचार-प्रसार करना जीवन का अंतिम उददेश्य है। इस अवसर पर, गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं भक्तों के लिए अनवरत लंगर, निःशुल्क चाय, नाश्ता भंडारे में मिल रहा आयोजित है। सवा महीने तक महाप्रसाद भंडारा का आयोजन किया गया। भगवती उपासक छत्रपति राजगुरु स्वामी हरि नारायण समदर्शी ने बताया कि यह भंडारा 3 जनवरी पौष पूर्णिमा से चला आ रहा है और मघी पूर्णिमा तक निरंतर चलता रहा।

भाजपा सांसद विपक्ष पर बरसे, कहा- यूपीए सरकार कई मोर्चों पर रही विफल

नई दिल्ली। भाजपा नेता तेजस्वी सूर्या ने सोमवार को लोकसभा में यूपीए सरकार की आलोचना की। उन्होंने यूपीए के दस साल के शासनकाल को खोए हुए अवसरों का दशक और कई मोर्चों पर विफल रहने के लिए बहानेबाजी का वृत्तांत करार दिया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि कमजोर नेतृत्व और महान नेतृत्व के बीच का अंतर ही कांग्रेस और भाजपा को अलग करता है।

भाजपा और कांग्रेस में फर्क- सूर्या

उन्होंने दावा किया कि यूपीए शासनकाल के दौरान राष्ट्रपति के भाषण में सरकार की कई मोर्चों पर विफलताओं के लिए बहानेबाजी झलकती थी। उन्होंने कहा कि कमजोर नेतृत्व बहाने बनाता है। वहीं, महान नेतृत्व चुनौतियों के बावजूद परिणाम देता है। उन्होंने कहा कि यही कांग्रेस और भाजपा के बीच मुख्य अंतर है। अपने भाषण के दौरान, बंगलूरू (दक्षिण) के सांसद ने कहा कि दुनिया के विभिन्न समृद्ध लोकतंत्रों में नेता आए और गए। वहीं नरेंद्र मोदी भारी बहुमत के साथ रिकॉर्ड तीसरी बार सत्ता में लौटे हैं।

सूर्या ने आतंकवाद और नक्सलवाद पर यूपीए सरकार के रुख पर भी हमला किया, जिससे विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच संक्षिप्त, तीखी बहस छिड़ गई। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार ने आतंकवाद से निपटने के लिए कुछ नहीं किया, जबकि मोदी सरकार ने सैन्य हमलों से जवाबी कार्रवाई की।

भाजपा नेता ने दावा किया कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में राष्ट्रपति के भाषण में देश की सांस्कृतिक परंपराओं और विरासत का कोई जिक्र नहीं था। कुछ कांग्रेस सदस्यों के विरोध के बाद, गृह मंत्री अमित शाह ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि सूर्या केवल राष्ट्रपति के भाषण की विषयवस्तु की बात कर रहे थे, किसी विशेष नेता की नहीं। केंद्रीय मंत्री सरबानंदा सोनोवाल ने धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया, जिसका सूर्या ने समर्थन किया।

माघ पूर्णिमा की शुभकामनायें : संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती पर उनकी राष्ट्र साधना को नमन

माघ पूर्णिमा केवल अनुष्ठानों का पर्व नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और अंतर्मन के जागरण का पर्व : स्वामी चिदानन्द सरस्वती

प्रयागराज/ऋषिकेश। पवित्र माघ पूर्णिमा के पुण्य अवसर पर समस्त देशवासियों, श्रद्धालुओं और कल्पवासियों को परमार्थ निकेतन से शुभकामनाएँ। माघ मास अत्यंत पवित्र होने के साथ तप, साधना, दान तथा स्नान का महीना है। इस मास में किए गए जप, तप, व्रत और तीर्थस्नान का फल अनेक गुना बढ़ जाता है, और माघ पूर्णिमा इसका परम मंगलमय समापन पर्व है।

माघ पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों विशेषकर गंगा, यमुना और संगम में स्नान करने से समस्त पापों का क्षय होता है तथा मन, वचन और कर्म की शुद्धि प्राप्त होती है। यह तिथि भगवान विष्णु एवं चंद्रदेव की आराधना के लिए विशेष है। इस दिन दान, हवन, सत्संग, कथा-श्रवण और भजन-कीर्तन के माध्यम से ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करे।

माघ पूर्णिमा केवल बाहरी अनुष्ठानों का पर्व नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और अंतर्मन के जागरण का भी संदेश देती है। यह हमें संयम, सेवा, करुणा और परोपकार की भावना से जीवन जीने की प्रेरणा प्रदान करती है। सनातन परंपरा में 'दान' और 'स्नान' के साथ 'ज्ञान' का विशेष महत्व है, जो आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर करती है।

आइए, हम सभी इस शुभ अवसर पर अपने जीवन में पवित्रता, सदाचार और धर्म के आदर्शों को अपनाने का संकल्प लें तथा राष्ट्र और समाज के कल्याण के लिए समर्पित हों। माघ पूर्णिमा की इस दिव्य बेला पर सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की परमार्थ निकेतन से मंगलमय शुभकामनाएँ।

उनका प्रसिद्ध संदेश 'मन चंगा तो कठौती में गंगा' संदेश देता है कि भक्ति बाहरी आडंबरों में नहीं, बल्कि निर्मल मन और शुद्ध आचरण में निहित है। आज भी उनके विचार सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं।

संत रविदास जी का जीवन प्रेरित करता है कि हम प्रेम, समानता और सेवा के मूल्यों को अपनाकर एक न्यायपूर्ण और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान दें। उनकी शिक्षाएँ वर्तमान समय में और भी प्रासंगिक हैं, जब समाज को आपसी सद्भाव और आध्यात्मिक जागृति की आवश्यकता है।

इस पावन अवसर पर हम संत रविदास जी की साधना को नमन करते हुये उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लें।

एचडीएफसीम्यूचुअल फंड ने शुरू कियानिवेशक जागरूकता अभियान

वाराणसी। एचडीएफसीम्यूचुअल फंड की निवेश प्रबंधक कंपनी एचडीएफसीएसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेडने इन दिनों प्रयागराज में चल रहे माघ मेला 2026 में निवेशक जागरूकता अभियान शुरू किया

है।3 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक आयोजित माघ मेले में चल रहे इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं के बीच वित्तीय साक्षरता बढ़ाना और अनुशासित, दीर्घकालिक निवेश को प्रोत्साहित करना है।

रेलवे लाइन पर युवती का मिला शव, क्षेत्र में फैली सनसनी

प्रयागराज। थरवई थाना क्षेत्र के गणेशपुर गांव के पास सोमवार सुबह रेलवे लाइन पर एक युवती का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बाद में मृतका की पहचान सुहानी तिवारी (21) निवासी नीवी गारापुर के रूप में हुई। परिजनों के अनुसार वह दो दिन पहले माघ मेले में कथा में शामिल होने गई थी और वहीं से लापता हो गई थी। घटनास्थल से मोबाइल फोन बरामद किया गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए परिजनों व अन्य संबंधित लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। मामले की जांच सभी पहलुओं से की जा रही है।

उत्तर प्रदेश रेल अवसंरचना का कायाकल्प

बजट 2026 में 20, 012 करोड़ का ऐतिहासिक आवंटन और 'कवच' प्रणाली से सुदृढ़ होगी सुरक्षा

प्रयागराज। रेल मंत्री, अश्विनी वैष्णव द्वारा बजट 2026-27 में रेल मंत्रालय को आवंटित बजट के संबंध में प्रेस वार्ता को संबोधित किया गया। माननीय मंत्रीजी द्वारा विभिन्न राज्यों में चल रही परियोजनाओं के विषय में विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से बताया कि सभी राज्यों को पूर्व में आवंटित होने वाले बजट से कई गुना अधिक धनराशि आवंटित की गई है। उन्होने बताया कि उत्तर प्रदेश में रेल नेटवर्क और यात्री सुविधाओं के आधुनिकीकरण में एक अभूतपूर्व क्रांति देखी जा रही है। केंद्रीय बजट 2026 में भारतीय रेल के लिए ?2.93 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के लिए ?20, 012 करोड़ का ऐतिहासिक आवंटन शामिल है। यह आवंटन वर्ष 2009-14 के औसत वार्षिक बजट (?1, 109 करोड़) की तुलना में 18 गुना अधिक है।

बुनियादी ढांचे में व्यापक निवेश और विस्तार राज्य में वर्तमान में ?92, 056 करोड़ की कुल लागत वाले कार्य प्रगति पर हैं, जिनमें ट्रैक निर्माण, स्टेशनों का पुनर्विकास और सुरक्षा संवर्धन शामिल हैं। वर्ष 2014 के बाद से लगभग 5, 500 किमी नए ट्रैक का निर्माण किया गया है और राज्य ने 100इ विद्युतीकरण का गौरवपूर्ण लक्ष्य हासिल कर लिया है। बुनियादी ढांचे को और गति देते हुए रेल बजट 2026 में 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है। हाल ही में अलीगढ़-दाउद खां के बीच तीसरी लाइन कमीशन की गई है और सबलगढ़-बीरपुर के बीच गेज कन्वर्जन का कार्य भी अंतिम चरण में है।

अमृत स्टेशन योजना और विश्वस्तरीय यात्री सुविधाएं यात्री अनुभव को आधुनिक बनाने के लिए 'अमृत स्टेशन योजना' के तहत उत्तर प्रदेश के 157 स्टेशनों की पहचान की गई है, जिस पर ?7, 746 करोड़ का निवेश किया जा रहा है। अयोध्या धाम, गोमती नगर और सहारनपुर जं. जैसे 22 स्टेशनों पर कार्य पूर्ण हो चुका है। उत्तर मध्य रेलवे परिक्षेत्र में प्रयागराज जंक्शन, कानपुर सेंट्रल,

वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी और ग्वालियर जैसे प्रमुख स्टेशनों का पुनर्विकास तीव्र गति से जारी है। इसके अतिरिक्त, अलीगढ़, आगरा और मथुरा स्टेशनों के पुनर्विकास का मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। सुरक्षा तकनीक 'कवच' और निर्बाध यात्रा रेलवे संरक्षा के लिए बजट 2026 में ?1.20 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं। स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली 'कवच' को तेजी से लागू किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में पलवल-मथुरा सेक्शन के 83 रूट किलोमीटर में कवच प्रणाली का कमीशनिंग किया जाएगा। अब तक 297 लोकोमोटिव में यह प्रणाली स्थापित की जा चुकी है। साथ ही, आवाजाही को सुगम बनाने के लिए राज्य में 1, 694 फ्लाईओवर और अंडरपास का निर्माण किया गया है। बढ़ती कनेक्टिविटीः वंदे भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस राज्य में प्रीमियम ट्रेन सेवाओं का विस्तार करते हुए वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 17 जोड़ी वंदे भारत और 18 जोड़ी अमृत भारत ट्रेनें संचालित हैं। विशेष रूप से उत्तर मध्य रेलवे ज़ोन में 16 वंदे भारत और 20 अमृत भारत एक्सप्रेस अपनी सेवाएं दे रही हैं। उत्तर प्रदेश में रेल सेवाओं का यह विस्तार न केवल कनेक्टिविटी को सुदृढ़ कर रहा है, बल्कि राज्य की आर्थिक प्रगति और यात्री सुरक्षा में भी मील का पत्थर साबित हो रहा है।

वर्ल्ड रीजनल एनेस्थीसिया एवं पेन मेडिसिन डे वर्कशॉप : रोगी सुरक्षा मानकों को मजबूत करने पर जोर

वाराणसी। बीडी (बेक्टन, डिकिन्सन एंड कंपनी) ने हाल ही में वर्ल्ड रीजनल एनेस्थीसिया एंड पेन मेडिसिन (आरएपीएम) डे वर्कशॉप में नॉलेज पार्टनर के रूप में भाग लिया। इस पहल के जरिए बीडी इंडिया/साउथ एशिया ने रीजनल एनेस्थीसिया में रोगी सुरक्षा को बेहतर बनाने पर जोर देते हुए चिकित्सकों के लिए रियल-टाइम, हैंड्स-ऑन लर्निंग का अवसर प्रदान किया।। कार्यक्रम के दौरान उन्नत चिकित्सीय उपकरणों और संसाधनों की सहायता से स्पाइनल एनेस्थीसिया तकनीकों का उपयोग किया गया और विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा लाइव प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए।

भिवंडी में आवारा कुत्ते के काटने से घायल 12 वर्षीय बच्चे की 20 दिन बाद मौत, शहर में आक्रोश

सपा विधायक ने अस्पताल पर लगाया लापरवाही का आरोप, सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी शहर में आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या ने एक बार फिर एक मासूम की जान ले ली है। ईदगाह इलाके में आवारा कुत्ते के काटने से घायल हुए 12 वर्षीय किशोर की करीब 20 दिनों तक इलाज चलने के बाद मौत हो गई। इस घटना के बाद न सिर्फ पीड़ित परिवार, बल्कि पूरे इलाके में आक्रोश और दहशत का माहौल है। वहीं समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ने सरकारी अस्पतालों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, ईदगाह इलाके में रहने वाले 12 वर्षीय हमीद सद्दाम खान पर 10 जनवरी को एक आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे तत्काल भिवंडी के सरकारी आईजीएम उपजिला अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे ठाणे सिविल अस्पताल रेफर किया गया, जहां से कुछ समय बाद फिर आईजीएम अस्पताल लाया

गया। उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी हालत स्थिर बताते हुए उसे घर भेज दिया था।

आईजीएम अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि बच्चे को एंटी-रेबीज वैक्सीन और टिटनेस का इंजेक्शन दिया गया था। हालांकि, कुछ सप्ताह बाद अचानक किशोर की तबीयत बिगड़ने लगी। हालत गंभीर होने पर परिजन उसे मुंबई के एक निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान 30 जनवरी को उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों के अनुसार, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मौत का सीधा कारण कुत्ते के काटने से फैला संक्रमण था या कोई अन्य चिकित्सकीय जटिलता।

इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि भिवंडी में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन प्रशासन और मनपा इस गंभीर समस्या को नजरअंदाज कर रहे हैं। विधायक ने आरोप लगाया कि सरकारी अस्पतालों में दवाओं की भारी कमी है और स्वास्थ्यकर्मी इलाज में लापरवाही बरत रहे हैं। उन्होंने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने की बात कही है।

भिवंडी शहर में आवारा कुत्तों का आतंक इस कदर बढ़ चुका है कि आम नागरिकों का सड़कों पर निकलना मुश्किल हो गया है। मनपा से जुड़े आंकड़ों के अनुसार, पिछले एक वर्ष में शहरभर में 11,037 लोग आवारा कुत्तों के काटने का शिकार हो चुके हैं। वहीं सिर्फ जनवरी 2026 में ही अब तक 1,062 लोगों पर कुत्तों ने हमला किया है। कई मामलों में दोपहिया वाहन चालकों को कुत्तों के पीछा करने से हादसों का भी सामना करना पड़ा है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि आवारा कुत्तों की धरपकड़ और नसबंदी (निर्बीजिकरण) का काम सही तरीके से नहीं हो रहा है। ठेकेदारों के कर्मचारी कभी-कभार ही सड़कों और गलियों में नजर आते हैं, जिससे कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यह स्थिति अब मानव सुरक्षा के लिए बेहद गंभीर चिंता का विषय बन चुकी है। इस घटना के बाद लोगों ने मनपा प्रशासन से आवारा कुत्तों पर तत्काल प्रभावी नियंत्रण, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है।

कृषि बजट की मांग को लेकर किसान सभा का आंदोलन, प्रधानमंत्री को सौंपा गया ज्ञापन

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

देश के कृषि क्षेत्र के लिए अलग से कृषि बजट पेश किए जाने की मांग को लेकर महाराष्ट्र राज्य किसान सभा की ओर से भिवंडी प्रांत अधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान किसान नेताओं ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले कृषि क्षेत्र की लगातार उपेक्षा हो रही है, जिसके कारण किसान गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं।

किसान सभा द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि बीज, खाद, कीटनाशक, बिजली और डीजल जैसी कृषि उत्पादन लागत लगातार बढ़ रही है, लेकिन किसानों को उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य नहीं मिल पा रहा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की प्रभावी गारंटी न होने से किसान कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे हैं। इसी आर्थिक तंगी के चलते देशभर में किसानों की आत्महत्याओं की घटनाएं चिंता का विषय बनी हुई हैं।

किसान नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार हर वर्ष विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग-अलग बजट प्रावधान करती है,

लेकिन कृषि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए अब तक स्वतंत्र और समर्पित कृषि बजट नहीं लाया गया है। यदि कृषि के लिए अलग बजट घोषित किया जाए, तो सिंचाई, फसल बीमा, भंडारण, विपणन और किसान कल्याण योजनाओं को मजबूती मिलेगी और किसानों को सीधी राहत पहुंचाई जा सकेगी।

इस अवसर पर किसान सभा के ठाणे जिला सचिव कॉमरेड रमेश जाधव, भिवंडी तालुका अध्यक्ष कॉमरेड बालाराम भोईर, महाराष्ट्र राज्य निर्माण कामगार फेडरेशन के राज्य कार्याध्यक्ष कॉमरेड डॉ. विजय कांबळे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के ठाणे जिला सहसचिव कॉमरेड इकबाल हुसैन खान सहित कॉमरेड मदार खान, कॉमरेड नामदेव काकड़े, कॉमरेड बबन विशे, कॉमरेड अताउल्ला खान, कॉमरेड समीर और बड़ी संख्या में किसान कार्यकर्ता उपस्थित थे.किसान सभा ने चेतावनी दी है कि यदि केंद्र सरकार ने कृषि बजट और किसानों की मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया, तो आने वाले समय में आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

भिवंडी में एटीएम मशीनों की सुरक्षा राम भरोसे, ठगी गिरोह सक्रिय

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी शहर में बैंकों द्वारा लगाए गए एटीएम मशीनों की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से राम भरोसे चल रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम न होने के कारण न सिर्फ एटीएम मशीन काटकर लाखों रुपये की चोरी हो रही है, बल्कि कार्ड एक्सचेंज कर खातों से पैसे उड़ाने वाला गिरोह भी सक्रिय हो गया है। लगातार सामने आ रही घटनाओं के बावजूद बैंक प्रबंधन और पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में है।

पुलिस के अनुसार ठाणे के बालकुम नाका निवासी ट्रांसपोर्ट व्यवसायी मानधाता शिवपुजन सिंह (57) 18 जनवरी 2026 को काल्हेर स्थित एचडीएफसी बैंक के एटीएम में पैसे निकालने गए थे। इसी दौरान वहां मौजूद एक अज्ञात व्यक्ति ने बातचीत के बहाने उनका ध्यान भटकाया और उनका एटीएम कार्ड बदल दिया। बाद में आरोपी ने पीड़ित के खाते से 75,500 रुपये निकाल लिए। खाते से पैसे कटने की जानकारी मिलने पर पीड़ित ने 31 जनवरी को नारपोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

भिवंडी लघु उद्योगों का प्रमुख केंद्र होने के कारण यहां लगभग सभी बैंकों की शाखाएं और सैकड़ों एटीएम मशीनें लगी हुई हैं, लेकिन अधिकांश एटीएम पर न तो सुरक्षा गार्ड तैनात हैं और न ही सीसीटीवी कैमरे ठीक से काम कर रहे हैं। इसी सुरक्षा के अभाव का फायदा उठाकर हाल ही में अंजुरफाटा के शिवाजीनगर इलाके में यूनियन बैंक के एटीएम को गैस कटर से काटकर करीब 9.90 लाख रुपये की चोरी की गई थी। इसी तरह कोनगांव इलाके में भी एटीएम काटकर करीब 10 लाख रुपये चुराए जा चुके हैं। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि एटीएम के आसपास असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है, जिससे कार्ड धारकों में भय का माहौल बना रहता है। पुलिस हर मामले में केस तो दर्ज करती है, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से लोगों का भरोसा डगमगा रहा है। शहरवासियों ने बैंकों से एटीएम सुरक्षा मजबूत करने और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है।

धारदार हथियार से गला काटकर किसान की निर्मम हत्या, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

लखनऊ **(एजेंसी)**। प्रदेश के मऊ जिले में सोमवार को एक खेत में 54 वर्षीय व्यक्ति का शव बरामद किया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि घटना सरायलाखंसी इलाके के गर्थोली गांव की है और व्यक्ति की गला रेतकर हत्या की गई थी। पुलिस के मुताबिक, खेत में काम कर रही महिलाओं ने शव देखा और शोर मचाया, जिसके बाद बड़ी संख्या में गांव वाले मौके पर जमा हो गए और पुलिस को घटना की सूचना दी गयी। अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने बताया कि मृतक की पहचान शिववचन कुमार के रूप में हुई है।

अवैध निर्माण से जुड़ी दो शिकायतें प्राप्त, कार्रवाई के निर्देश

भिवंडी महानगरपालिका में लोकशाही दिवस संपन्न

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी। महाराष्ट्र शासन के निर्देशानुसार भिवंडी-निजामपुर शहर महानगरपालिका में सोमवार 2 फरवरी 2026 को लोकशाही दिवस का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम महानगरपालिका मुख्यालय स्थित नई प्रशासकीय इमारत के तीसरे मंजिल पर आयुक्त सभागृह में आयोजित हुआ। लोकशाही दिवस की अध्यक्षता अतिरिक्त आयुक्त विठ्ठल डाके ने की।

इस दौरान नागरिकों की ओर से कुल दो शिकायत अर्ज प्राप्त हुए। दोनों शिकायतें अवैध निर्माण से संबंधित थीं। अतिरिक्त आयुक्त विठ्ठल डाके ने प्राप्त शिकायतों पर गंभीरता से विचार करते हुए संबंधित विभाग प्रमुखों को आवश्यक व त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। महानगरपालिका प्रशासन की ओर से बताया गया कि अगला लोकशाही दिवस सोमवार 2 मार्च 2026 को सुबह 11 बजे आयोजित किया जाएगा। यह भी कार्यक्रम नई प्रशासकीय इमारत, तीसरी मंजिल स्थित आयुक्त सभागृह में ही संपन्न होगा। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि जो भी आवेदक लोकशाही दिवस के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं, वे निर्धारित नमूने में अपनी शिकायत के तीन प्रतियों के साथ 13 फरवरी 2026 से पहले महानगरपालिका के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में आवेदन जमा करें।

सार्वजनिक मंचों पर पार्टी विरोधी बयानबाजी करने वालों पर गिरेगी गाज

भाजपा बोली- बगावती तेवर अब नहीं होंगे बर्दाश्त

लखनऊ **(एजेंसी)**। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन को लेकर सख्त रुख अपनाया गया है। पार्टी कार्यक्रमों और सार्वजनिक मंचों पर बगावती तेवर दिखाने वाले नेताओं और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई की तैयारी है। सूत्रों के अनुसार, ऐसे नेताओं से जवाब तलब किया जाएगा और संतोषजनक स्पष्टीकरण न मिलने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई तय मानी जा रही है।

यूपी भाजपा की अनुशासन समिति जल्द ही ऐसे नेताओं और पदाधिकारियों को नोटिस जारी करेगी, जिन्होंने हाल के दिनों में पार्टी लाइन से हटकर बयानबाजी की है या सार्वजनिक रूप से नाराज़गी जाहिर की है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि इस तरह की बयानबाजी से न सिर्फ संगठनात्मक एकता प्रभावित हो रही है, बल्कि जनता के बीच पार्टी की छवि को भी नुकसान पहुंच रहा है।

बीते कुछ समय में कई विधायक, जनप्रतिनिधि और संगठन से जुड़े पदाधिकारी खुलेआम सरकार और संगठन के कामकाज पर सवाल उठाते नजर आए हैं। विकास कार्यों, संगठनात्मक फैसलों और आपसी समन्वय को लेकर सामने आ रही असंतोष की आवाजों ने हाईकमान की चिंता बढ़ा दी है। खासतौर पर 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी किसी भी तरह का आंतरिक नुकसान उठाने के मूड में नहीं है।

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, अब सार्वजनिक मंचों पर अनुशासनहीनता या नेतृत्व के खिलाफ बयान देने को गंभीरता से लिया जाएगा। अनुशासन समिति ऐसे मामलों पर पैनी नजर रखे हुए है और जरूरत पड़ने पर उदाहरणात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। नेतृत्व का स्पष्ट संदेश है कि संगठन के भीतर अपनी बात रखने के लिए पार्टी के आंतरिक मंच मौजूद हैं, लेकिन सार्वजनिक बयानबाजी स्वीकार नहीं की जाएगी।

भाजपा नेतृत्व ने विकास कार्यों की गति और संगठन में बढ़ती आपसी कलह को लेकर भी निगरानी तेज कर दी है। पार्टी का मानना है कि आंतरिक एकजुटता के बिना चुनावी सफलता संभव नहीं है। ऐसे में अनुशासन समिति अब सख्ती के मूड में है और आने वाले दिनों में इस दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकते हैं।

सस्पेंड पीसीएस अलंकार अग्निहोत्री का खुला ऐलान!

सात फरवरी से करेंगे देशव्यापी आंदोलन सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम

वाराणसी **(एजेंसी)**। बरेली के नगर मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देने के बाद सुर्खियों में आए 2019 बैच के प्रांतीय प्रशासनिक सेवा (पीसीएस) अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने रविवार को घोषणा की कि यदि केंद्र सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम वापस नहीं लेती है तो वह सात फरवरी से दिल्ली में सवर्ण समाज के संगठनों के साथ आंदोलन करेंगे। इस्तीफा देने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निलंबित किए गए पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री रविवार शाम वाराणसी के केदार घाट स्थित श्रीविद्या मठ पहुंचे, जहां उन्होंने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। यहां उन्होंने कहा कि यदि केंद्र सरकार छह फरवरी तक एससी-एसटी अधिनियम को वापस नहीं लेती है तो वह सात फरवरी को सवर्ण समाज के संगठनों के साथ दिल्ली में आंदोलन करेंगे।

शंकराचार्य से मुलाकात को लेकर पूछे गए सवाल पर अग्निहोत्री ने कहा कि यह भेंट एक शुभ संयोग है और इसका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे पहले शंकराचार्य ने उन्हें प्रयागराज में मिलने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन समय के अभाव में वह नहीं जा सके थे। काशी आगमन के दौरान उनसे मुलाकात का अवसर मिला। अग्निहोत्री ने कहा, "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नए नियमों को लेकर लोगों में आक्रोश है और सरकार का बड़ा मतदाता वर्ग इससे नाराज है।" उन्होंने एससी/एसटी अधिनियम को 1989 में लागू किया गया देश का 'सबसे काला कानून' करार देते हुए दावा किया कि इससे 85 प्रतिशत लोग प्रभावित हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि एससी/एसटी कानून के 95 प्रतिशत मामले फर्जी होते हैं और पूरे देश के सवर्ण समाज के संगठन उनके साथ खड़े हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बरेली के नगर मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को अनुशासनहीनता के आरोप में 26 जनवरी की देर रात निलंबित कर दिया था। इससे पहले उन्होंने 26 जनवरी को दिन में सरकार की नीतियों, विशेषकर यूजीसी के नए नियमों और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े एक मामले को लेकर नाराजगी जताते हुए पद से इस्तीफा दे दिया था, जिससे प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर विवाद खड़ा हो गया।

इस्तीफा वापस लेने पर भड़के अविमुक्तेश्वरानंद

बोले- जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत सिंह ने थूककर चाटा

अयोध्या **(एजेंसी)**। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अयोध्या के जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत सिंह इस्तीफा वापस लेने पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बरेली मजिस्ट्रेट के इस्तीफा देने के बाद जो त्यागपत्र दिलवाया गया था। वह वापस हो चुका है। आदमी थूक कर चाट चुका है। हमने तभी कहा था कि ये जो त्यागपत्र दिया गया है वो चार दिन में वापस होगा। और वही हुआ।

पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह के बयान उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि मंत्री आका शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। आका अरबी शब्द है। उन्हें पता नहीं कि शंकराचार्य सर्वोच्च पद है। उसके ऊपर कोई नहीं हो सकता है। तुम्हारे आका हो सकते हैं। तुम मंत्री हो, तुम्हारे आका मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री के आका राज्यपाल और केंद्र में मंत्री हैं। तुम्हारी मुसलमानी भाषा बता रही है कि सब कुछ मुगलिया हो चुका है। आप को बता दें कि सीएम योगी पर विवादित टिप्पणी के बाद आहत होकर अयोध्या के जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत सिंह ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि यह कदम मैं किसी के दबाव में नहीं ले रही हूं बल्कि अपनी मर्जी से ले रहा हूं।

सिंह के इस्तीफे के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल मच गई। प्रशांत सिंह के भाई ने फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट के सहारे जीएसटी डिप्टी कमिश्नर के पद पर नौकरी हथियाने का आरोप लगाया। फिलहाल प्रशांत कुमार सिंह ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में अपनी नौकरी फिर से शुरू कर दी है। अब उन पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद हमला बोला है।

विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में पंचायत चुनाव!

आरक्षित वर्ग को बड़ी राहत, मंत्री ओपी राजभर ने दिया साफ संकेत

लखनऊ **(एजेंसी)**। प्रदेश में पंचायत चुनाव कब होंगे, इसे लेकर लोगों में काफी समय से उत्सुकता बनी हुई है। इस बीच राज्य के पंचायत राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले ही यूपी में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे।

राजभर के मुताबिक, जैसे ही विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया पूरी होगी, उसके बाद लगातार चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चर्चा है कि पंचायत चुनाव अप्रैल से जुलाई 2026 के बीच कराए जा सकते हैं। हालांकि,

आधिकारिक तारीखों की घोषणा चुनाव आयोग की ओर से ही की जाएगी।

सरकार ने पंचायत चुनाव लड़ने वाले ओबीसी, एससी, एसटी और अन्य आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी है। सामान्य वर्ग की तुलना में इन्हें नामांकन शुल्क और जमानत राशि में 50इ की छूट मिलेगी। यह वह फीस है जो उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के लिए नामांकन करते समय देनी होती है। यह राशि वापस नहीं होती।

यह सुरक्षा राशि होती है। यदि उम्मीदवार चुनाव में पर्याप्त वोट (आमतौर पर कुल वैध वोटों का 1/6 हिस्सा) नहीं पा पाता, तो यह राशि जब्त हो जाती है। लेकिन अगर उम्मीदवार तय वोट हासिल कर ले या नामांकन वापस ले ले, तो यह राशि वापस मिल जाती है।

यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज होने वाली है। आरक्षण वर्ग को दी गई छूट से बड़ी संख्या में उम्मीदवार मैदान में उतर सकते हैं। अब सभी की नजर चुनाव आयोग की आधिकारिक घोषणा पर टिकी है।

टी20 विश्व कप में भारत से खेलने से पाकिस्तान का इनकार, कीर्ति आजाद बोले- 'हार के डर से भागे'

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने कहा कि पाकिस्तान ने आगामी आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के ग्रुप चरण के मैच में भारत के खिलाफ खेलने से इनकार कर दिया है क्योंकि उन्हें पता है कि वे मैच नहीं जीत सकते। कीर्ति आजाद ने कहा कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ टी20 विश्व कप मैच का बहिष्कार कर रहा है क्योंकि वे मैच जीत नहीं सकते। उन्होंने यह भी कहा कि 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकवाद के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय संदेश देने के लिए भारत को विश्व कप से हट जाना चाहिए था।

कीर्ति आजाद ने कहा कि पाकिस्तान जानता है कि वह जीत नहीं सकता। इसलिए उसने अपनी इज्जत बचाने का सोचा... जब बैसरन (पहलगाम की घाटी) में 26 लोग मारे गए थे, तब भारत के पास एक बड़ा मौका था। भारत को तब विश्व कप में नहीं खेलना चाहिए था... इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह संदेश जाता कि हम आतंकवादियों के खिलाफ हैं और पाकिस्तान सबसे बड़ा आतंकवादी देश है। भाजपा सांसद शशांक मणि ने कहा कि जब किसी खिलाड़ी को एहसास होता है कि वह जीत नहीं सकता, तो वह मैदान से भाग जाता है। वे 'रांचछोड़' हैं, वे मैदान से भाग गए हैं। अगर आप किसी चैंपियनशिप में भाग ले रहे हैं, तो आपको बिना किसी भेदभाव के खेलना चाहिए। हमने उन्हें ऑपरेशन सिंदूर और अन्य

युद्धों में हराया था। हम उन्हें यहां भी हरा सकते थे। इसलिए वे खेल भी नहीं रहे हैं।

सांसद की यह टिप्पणी तब आई है जब पाकिस्तान ने 15 फरवरी को होने वाले आईसीसी विश्व टी20 विश्व कप में भारत के खिलाफ अपने ग्रुप स्टेज मैच का बहिष्कार करने का फैसला किया है। पाकिस्तान सरकार ने ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा कि पाकिस्तान टीम भारत के खिलाफ मैच में मैदान पर नहीं उतरेगी। रविवार को ट्विटर पर एक पोस्ट में पाकिस्तान सरकार ने कहा कि इस्लामिक गणराज्य पाकिस्तान की सरकार आईसीसी विश्व टी20 2026 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की भागीदारी को मंजूरी देती है; हालांकि, पाकिस्तान क्रिकेट टीम 15 फरवरी 2026 को भारत के खिलाफ निर्धारित मैच में मैदान पर नहीं उतरेगी।

पाकिस्तान सरकार ने भारत के खिलाफ न खेलने के अपने फैसले का कोई कारण नहीं बताया। भारतीय टीम विश्व कप से पहले शानदार फॉर्म में है और उसने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज 4-1 से जीती है। पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ टी20 विश्व कप के ग्रुप स्टेज मैच का बहिष्कार करने के कुछ घंटों बाद, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने कहा कि चुनिंदा भागीदारी वैश्विक खेल आयोजन के मूल सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है और वह पीसीबी से सभी हितधारकों के हितों की रक्षा करने वाले पारस्परिक समाधान की तलाश करने की अपेक्षा करती है।

'बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना', पाकिस्तान के मैच बहिष्कार पर हरभजन सिंह ने जमकर लताड़ा

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ टी20 विश्व कप के ग्रुप चरण के मैच का बहिष्कार करने की कड़ी आलोचना की और पूछा कि इस कदम से इस्लामाबाद को क्या लाभ होगा। उन्होंने कहा कि यह कदम लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से उठाया गया है, ताकि वे यह न सोचें कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा है। पाकिस्तान ने आईसीसी टी20 विश्व कप में 15 फरवरी को होने वाले ग्रुप चरण के मैच में भारत के खिलाफ खेलने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान सरकार ने एक पोस्ट में कहा कि पाकिस्तानी टीम भारत के खिलाफ मैच में नहीं उतरेगी, बिना कोई कारण बताए। यह मैच 15 फरवरी को होना था। पाकिस्तान इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में ग्रुप 'ए' में भारत, नामीबिया, नीदरलैंड और अमेरिका के साथ है।

गौरतलब है कि यह घटना बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचारों के मद्देनजर बीसीसीआई के निर्देश पर कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) द्वारा तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को टीम से बाहर किए जाने के बाद स्कॉटलैंड द्वारा भारत में मैच खेलने से इनकार करने के कुछ ही दिनों बाद हुई है। अपने यूट्यूब चैनल

पर बोलते हुए हरभजन ने कहा, 'बेगानी की शादी में अब्दुल दीवाना। इस फैसले का कोई तर्क या उचित आधार नहीं है। इससे आपको क्या फायदा होगा? यह सिर्फ अहंकार दिखाने के लिए है। अगर आपको सच में लगता है कि आप ऐसा कर सकते हैं, तो अड़े रहिए। देखते हैं कि आपमें वाकई हिम्मत है या नहीं।'

हरभजन ने देश पर आरोप लगाया कि वह लोगों को यह जताने के लिए नाटक रच रहा है कि वे बांग्लादेश के साथ एकजुटता दिखा रहे हैं और सवाल किया कि क्या उन्होंने उन लोगों के बारे में सोचा है जो मैच देखना चाहते थे। उन्होंने आगे कहा कि यह पूरी तरह से एक नाटक है जो लोगों को यह जताने के लिए रचा गया है कि वे बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपने अपने देश के उन लोगों के बारे में क्या सोचा है जो भारत-पाकिस्तान मैच देखना चाहते हैं?

हरभजन ने कहा कि विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि मैच एक तटस्थ स्थान पर, यानी सह-मेजबान देश श्रीलंका के कोलंबो में खेला जाना था। पूर्व स्पिनर ने सवाल उठाया कि पाकिस्तान ने पिछले साल एशिया कप में भारत के खिलाफ अपने मैच दोनों देशों के बीच तनाव के बावजूद क्यों खेले और क्या यह कदम राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया था।

यूपीआई यूजर्स के लिए बड़ी खबर, सरकार ने बताया- लेनदेन पर लगेगी फीस या मिलेगी मुफ्त सर्विस

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। यूपीआई से लेनदेन अब कैश की तुलना में कई गुना बढ़ चुका है। इसके साथ ही इस डिजिटल सिस्टम को चलाने की लागत भी सरकार के लिए बढ़ती जा रही है। बीते कुछ महीनों से यूपीआई पर फीस लगाए जाने की अटकलें तेज थीं लेकिन अब सरकार ने इस पर अपना रुख पूरी तरह साफ कर दिया है, जिसका सीधा असर देश के करोड़ों लोगों पर पड़ेगा।

वित्तीय सेवा सचिव एम. नागराजू ने सोमवार को कहा कि यूपीआई (एकीकृत भुगतान इंटरफेस) के जरिए लेनदेन आगे भी पूरी तरह मुफ्त रहेगा और इसके संचालन पर आने वाला खर्च सरकार खुद वहन करेगी। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में यूपीआई को सपोर्ट देने के लिए 2, 000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ताकि इस पर आने वाले खर्च को सब्सिडी के जरिए पूरा किया जा सके।

गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी बजट 2026-27 में यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड के लिए 2, 000 करोड़ रुपए की सब्सिडी का ऐलान किया है। इससे पहले 2025-26 के संशोधित अनुमान में यह राशि 2, 196 करोड़ रुपए थी।

साइबर धोखाधड़ी को लेकर नागराजू ने कहा कि बैंकों की तकनीकी गड़बड़ी के कारण होने वाले फ्रॉड की हिस्सेदारी 3 फीसदी से भी कम है। उन्होंने जोर दिया कि आम लोगों की सतर्कता से साइबर फ्रॉड की घटनाओं को काफी हद तक रोका जा सकता है।

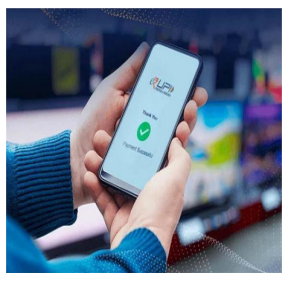

विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बैंकों के लिए बजट में एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति के गठन का प्रस्ताव भी रखा गया है। नागराजू ने बताया कि पहले समिति के कामकाज के नियम और शर्तें तय की जाएंगी, उसके बाद इसका गठन किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि फिलहाल भारतीय बैंक मजबूत स्थिति में हैं– एनपीए कम है और मुनाफा बेहतर है। उनके मुताबिक, भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए 3 से 4 बड़े बैंकों की जरूरत है, जिसे छोटे बैंकों के विलय के जरिए हासिल किया जा सकता है।

वित्त मंत्रालय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में एफडीआई सीमा 20 फीसदी से बढ़ाकर 49 फीसदी करने पर विचार कर रहा है। इस प्रस्ताव को लेकर मंत्रालयों के बीच परामर्श जारी है। फिलहाल निजी बैंकों में एफडीआई की सीमा 74 फीसदी है, जबकि सरकारी बैंकों में यह 20 फीसदी तक सीमित है।

भारत से मैच के बहिष्कार पर भड़के विराट कोहली के कोच, आईसीसी एक्शन की दी चेतावनी

मुंबई **(एजेंसी)**। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बार फिर विवाद खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान ने साफ कर दिया है कि वह 15 फरवरी को भारत के खिलाफ होने वाले ग्रुप स्टेज मुकाबले का बहिष्कार करेगा। हालांकि पाकिस्तान ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह टूर्नामेंट में हिस्सा लेगा, लेकिन भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा।

पाकिस्तान का यह फैसला ऐसे समय आया है जब पहले ही उनके वर्ल्ड कप में खेलने को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी।

इस पूरे मामले पर अब विराट कोहली के बचपन के कोच राजकुमार शर्मा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एएनआई से बातचीत में पाकिस्तान के फैसले को अजीब और दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया।

राजकुमार शर्मा ने कहा, 'यह बहुत अनफॉर्चुनेट है और पाकिस्तान का फैसला बेहद अजीब है। अब तक उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया था। पहले उन्होंने बांग्लादेश के समर्थन में वोट किया कि बांग्लादेश भारत में न खेले और अब खुद ही बैकआउट करने की बात कर रहे हैं।'

उन्होंने आगे कहा कि इस फैसले से पाकिस्तान को हर स्तर पर नुकसान उठाना पड़ेगा। 'इससे पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आवाम को और खिलाड़ियों को बहुत नुकसान होगा। पाकिस्तान की जनता भारत के खिलाफ अपने खिलाड़ियों को खेलते देखना चाहती है। यह खिलाड़ियों और फैंस, दोनों के लिए बड़ा नुकसान है। मुझे लगता है कि पीसीबी को इस फैसले पर दोबारा सोचना चाहिए।'

गावस्कर की पाकिस्तान क्रिकेट को चेतावनी भारत के खिलाफ मैच छोड़ना पड़ेगा भारी

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। भारतीय क्रिकेट के दिग्गज सुनील गावस्कर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के उस फैसले पर जमकर निशाना साधा है, जिसमें उसने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ होने वाले मुकाबले का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। यह मैच 15 फरवरी को खेला जाना था। पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक एक्स अकाउंट के जरिए इस फैसले की पुष्टि की गई, जिसके बाद से यह मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है।

हालांकि पाकिस्तान को टूर्नामेंट में खेलने की अनुमति मिल चुकी है, लेकिन उसने खास तौर पर भारत के खिलाफ मैदान पर न उतरने का फैसला लिया है।

एक्सक्लूसिव बातचीत में सुनील गावस्कर ने कहा कि अगर पाकिस्तान अपने फैसले से पलट जाता है तो इसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। 'मुझे लगता है कि अगले चार-पांच दिनों में जब दुनियाभर से और उनके पूर्व खिलाड़ियों की प्रतिक्रियाएं आएंगी, तो पाकिस्तान अपने रुख में बदलाव कर सकता है।'

उन्होंने आगे तंज कसते हुए कहा, 'इसमें नया क्या है? हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के खिलाड़ी संन्यास लेते हैं और फिर कुछ ही दिनों में वापस आ जाते हैं, यह कहते हुए कि फैंस ने कहा है खेलने के लिए। यू-टर्न लेना उनके लिए आम बात है। 15 फरवरी से पहले भी ऐसा हो सकता

है।' गावस्कर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) से भी इस पूरे मामले में कड़ा रुख अपनाने की अपील की। उनका कहना है कि अगर पीसीबी भारत के खिलाफ मैच से हटने का कोई ठोस और वैध कारण नहीं बता पाता, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए।

'अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ इतने बड़े मैच से हटने का कोई सही कारण नहीं दे पाता या कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की वजह नहीं दिखा पाता, तो आईसीसी को कार्रवाई करनी चाहिए, ' गावस्कर ने साफ शब्दों में कहा।

निर्यातकों ने बजट का किया स्वागत, विनिर्माण पर ध्यान देने से निर्यात को मिलेगी गति

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। आम बजट 2026-27 का स्वागत करते हुए निर्यातकों ने कहा कि कंटेनर उत्पादन के लिए योजना और सीमा शुल्क के युक्तिकरण जैसी कई घोषणाएं घरेलू विनिर्माण और देश के निर्यात को बढ़ावा देने में मददगार साबित होंगी। निर्यातकों ने कहा कि वैश्विक व्यापार में तनाव और अंतरराष्ट्रीय बाजार की चुनौतियों के बीच बजट प्रस्तावों से घरेलू उद्योग को काफी सहारा मिलेगा। उद्योग निकाय सीआईआई की निर्यात संबंधी राष्ट्रीय समिति के चेयरमैन और पैटन इंटरनेशनल लिमिटेड के प्रबंध निदेशक संजय बुधिया ने कहा कि आम बजट 2026-27 देश की वृद्धि क्षमता को उजागर करने वाला एक सकारात्मक संकेत है।

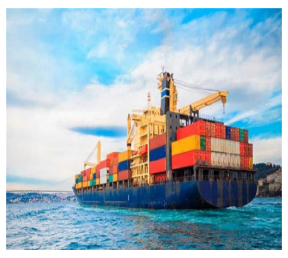

उन्होंने कहा, ''विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी कंटेनर विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए प्रस्तावित 10, 000 करोड़ रुपए की योजना एक समय पर लिया गया रणनीतिक फैसला है।'' परिधान निर्यात संवर्धन परिषद (एईपीसी) के चेयरमैन ए शक्तिवेल ने भी कहा कि सीमा शुल्क से जुड़े सुधारों और सरल दस्तावेजीकरण प्रक्रियाओं से लेनदेन की लागत कम होगी और निर्यातकों के लिए व्यापार करने में आसानी होगी।

शक्तिवेल के अनुसार विश्वसनीय आयातकों की पहचान, कम कार्गो सत्यापन और इलेक्ट्रॉनिक सीलिंग का उपयोग करके फैक्ट्री से बंदरगाह तक निपटान जैसे उपायों से लॉजिस्टिक लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी। स्वास्थ्य क्षेत्र की घोषणाओं पर टिप्पणी करते हुए कैरिंग माइंड्स इंटरनेशनल की संस्थापक मीनू बुधिया ने बजट में 'निमहंस 2.0' की स्थापना सहित विशिष्ट देखभाल तक पहुंच बढ़ाने के प्रस्ताव का स्वागत किया।

एफपीआई ने भारतीय बाजार से जनवरी में 36, 000 करोड़ रुपए निकाले, आगे एसटीटी से जोखिम

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की बिकवाली का सिलसिला जनवरी में भी जारी रहा और उन्होंने भारतीय शेयर बाजार से करीब 36, 000 करोड़ रुपए (लगभग 3.97 अरब डॉलर) की निकासी की। इस बीच, वायदा एवं विकल्प (एफएंडओ) खंड में सौदों पर प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) बढ़ाने की बजट घोषणा से निकट भविष्य में विदेशी निवेशकों की भागीदारी पर दबाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।

नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के आंकड़ों के मुताबिक, एफपीआई ने जनवरी महीने में भारतीय शेयर बाजार से 35, 962 करोड़ रुपए की शुद्ध निकासी की। एफपीआई ने इससे पहले वर्ष 2025 में भी भारतीय बाजार से करीब 1.66 लाख करोड़ रुपए (18.9 अरब डॉलर) की रिकॉर्ड निकासी की थी। उस समय अस्थिर मुद्रा बाजार, वैश्विक व्यापार तनाव, संभावित अमेरिकी शुल्क और ऊंचे बाजार मूल्यांकन ने विदेशी पूंजी को प्रभावित किया था। चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के तकनीकी शोध विश्लेषक आकाश शाह ने कहा कि एफएंडओ में एसटीटी का बढ़ना निकट अवधि में खासकर अत्यधिक तेजी और डेरिवेटिव-केंद्रित वैश्विक कोषों के लिए एफपीआई प्रवाह के लिए हल्का नकारात्मक कारक बन सकता है।

उन्होंने कहा, ''एसटीटी बढ़ोतरी से कर संग्रह बढ़ सकता है लेकिन इससे सौदों की मात्रा प्रभावित होने और रणनीतिक एफपीआई भागीदारी धीमी होने का जोखिम है। टिकाऊ एफपीआई प्रवाह के लिए निवेशक सिर्फ वृद्धि संभावनाओं के बजाय व्यापक स्थिरता, रुपए की चाल और कर नीति में निरंतरता पर अधिक ध्यान देंगे।'' वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2026-27 के बजट भाषण में वायदा पर एसटीटी को 0.02 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.05 प्रतिशत तथा विकल्प प्रीमियम एवं विकल्प सौदों पर एसटीटी को क्रमशः 0.10 प्रतिशत एवं 0.125 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा है। एंजेल वन लिमिटेड के वरिष्ठ बुनियादी विश्लेषक वकारजावेद खान ने कहा कि अमेरिका-यूरोप व्यापार तनाव, ग्रीनलैंड विवाद से जुड़ी शुल्क धमकियों, मजबूत डॉलर, ऊंचे बॉन्ड प्रतिफल, रुपए के 90-92 प्रति डॉलर के स्तर पर आ जाने और बाजार के उच्च मूल्यांकन ने भी जोखिम से बचाव की प्रवृत्ति बढ़ाई है। मॉर्निंगस्टार इन्वेस्टमेंट रिसर्च इंडिया के प्रमुख एवं शोध प्रबंधक हिमांशु श्रीवास्तव ने कहा कि विकसित बाजारों में ऊंची ब्याज दरें, मजबूत डॉलर और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के चलते उभरते बाजारों के प्रति जोखिम लेने की क्षमता घटी है। उन्होंने कहा कि घरेलू स्तर पर कंपनियों के नतीजों के मिले-जुले रुझान और बजट जैसी प्रमुख घटनाओं को लेकर सतर्कता ने भी विदेशी निवेशकों को सजग बनाए रखा।

क्रैश के बाद जबरदस्त कमबैक! एमसीएक्स-कॉमेक्स पर सोने की कीमतों में तेजी, 2388 रुपए महंगा हुआ सोना

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। सोने के बाजार में पिछले 48 घंटों के दौरान जो हलचल देखने को मिली है। कल और आज सुबह की भारी बिकवाली के बाद दोपहर के सत्र में कीमतों में अचानक रिकवरी दर्ज की गई। बाजार में आई इस वापसी को विशेषज्ञ डेड कैट बाउंस या फिर निचले स्तरों पर वैल्यू बाइंग का नतीजा मान रहे हैं।

एमसीएक्स पर सोने की कीमतों में शाम करीब 6 बजे के बाद 2388 रुपए यानी 1.62 फीसदी की तेजी दर्ज की गई। इस उछाल के बाद सोने का भाव बढ़कर 1, 50, 141 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया।

हालांकि चांदी में गिरावट का सिलसिला अब भी जारी है लेकिन बिकवाली की रफ्तार पहले के मुकाबले धीमी हुई है। एमसीएक्स पर मार्च कॉन्ट्रैक्ट वाली चांदी की कीमत 6, 789 रुपए यानी 2.56 फीसदी टूटकर 2, 58, 863 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। वहीं इंटरनेशनल मार्केट में दोनों कीमती धातुओं में तेजी दर्ज की गई है।

हालिया सत्रों में सोने-चांदी की कीमतों में 20-30 फीसदी तक की तेज गिरावट आई थी। ऐसे में बड़े ज्वेलर्स और दीर्घकालिक निवेशकों ने निचले स्तरों को खरीदारी का मौका माना, जिससे बाजार को सपोर्ट मिला।

गिरावट पर दांव लगाने वाले सट्टेबाजों ने मुनाफावसूली के लिए अपनी शॉर्ट पोजीशन कवर की। इस शॉर्ट कवरिंग से डिमांड बढ़ी और कीमतों में रिकवरी देखने को मिली।

80 करोड़ का 'ताज महल डायमंड नेकलेस' पहनकर छाईं मार्गो रॉबी

मार्गो रॉबी ने अपनी पहचान दुनियाभर में बनाई है। मार्गो रॉबी एक ऑस्ट्रेलियन एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में एक्ट्रेस काफी चर्चा में है और उनकी कुछ फोटोज भी इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं। इस बार रॉबी चर्चा में आने का कारण उनकी कोई फिल्म नहीं, बल्कि उनका एक शाही नेकलेस है। दरअसल, मार्गो अपनी अपकमिंग फिल्म 'वर्थरिंग हाइट्स' के प्रीमियर पर पहुंची थीं। इस ईवेंट में वह एक बेहद आकर्षक गाउन पहनकर पहुंचीं, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान उनके गले में सजे शानदार नेकलेस ने खींचा।

यह रॉयल हार देखते ही देखते चर्चा का केंद्र बन गया। कहा गया कि यह वही मशहूर नेकलेस है जो दिग्गज ब्रिटिश-अमेरिकन अभिनेत्री एलिजाबेथ टेलर से जुड़ा रहा है। हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि इस शाही ज्वेलरी का गहरा संबंध भारत और मुगल वंश के इतिहास से भी जुड़ा हुआ है। अब सवाल उठता है कि यदि इस हार का रिश्ता भारत से है, इसे मुगल बादशाहों ने अपनी बेगमों को दिया था, तो यह विदेशी एक्ट्रेस के पास कैसे आया है।

बता दें कि, मार्गो रॉबी एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर हैं। उन्होंने अपनी अकमिंग फिल्म के प्रीमियर में 'ताज महल डायमंड नेकलेस' वियर किया है, जो इंटरनेट पर काफी वायरल हो रहा है। यह नेकलेस जेड स्टोन से बना हुआ है। जेड स्टोन में कस्टम गोल्ड, रूबी और डायमंड चेन जड़ा ये हार्ट शेप नेकलेस हॉलीवुड एक्ट्रेस एलिजाबेथ का है। इनका 79 वर्ष की उम्र में उनके निधन के बाद भी यह नेकलेस इतिहास में अपनी खास पहचान बनाए हुए है। इससे जुड़ी कई रोचक कहानियां दर्ज हैं।

कहा जाता है कि एक समय यह कीमती नेकपीस रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था, लेकिन बाद

में यह एक मशहूर लग्ज़री ज्वेलरी ब्रांड के पास पाया गया। यह वहां कैसे पहुंचा, इसका खुलासा आज तक नहीं हो सका है। बताया जाता है कि एलिजाबेथ टेलर के पति ने यह हार उनके 40वें जन्मदिन पर उपहार में दिया था। साल 2011 में एलिजाबेथ टेलर की संपत्ति की नीलामी के दौरान इस शाही नेकलेस को करीब 80 करोड़ रुपये में बेचा गया था। यह 'ताज महल डायमंड नेकलेस'का सीधा कनेक्शन भारत से है। ये जिस रत्न यानी हरिताश्म (जेड स्टोन) से बना है। इसको धन और लक का प्रतीक माना जाता है। आपको बता दें कि, इस हार पर फारसी भाषा में लिखा है- प्यार अमर है। इस नेकलेस पर मुगल बेगम नूरजहां का नाम भी अंकित है। नूरजहां को उनके पति मुगल सम्राट जहांगीर ने ये हार दिया था। फिर शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज ने ये शाही हर गिफ्ट दिया था। मुमताज की मौत के बाद उनकी याद में ताजमहल बना और इसलिए इसको 'ताज महल डायमंड नेकलेस'का नाम दिया गया है।

क्या रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा उदयपुर में कर रहे हैं शादी? वायरल वीडियो ने मचाया तहलका

साउथ फिल्म इंडस्ट्री की सबसे चर्चित जोड़ी, रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा, एक बार फिर अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं। सोशल मीडिया पर एक ब्लॉगर द्वारा साझा किए गए वीडियो ने प्रशंसकों के बीच खलबली मचा दी है। दावा किया जा रहा है कि राजस्थान के उदयपुर में इस जोड़ी की शादी की भव्य तैयारियां चल रही हैं। इंटरनेट पर तेजी से फैल रहे इस वीडियो में उदयपुर की एक आलीशान 'लक्जरी प्रॉपर्टी' को फूलों और रोशनी से सजते हुए दिखाया गया है। वीडियो बनाने वाले शख्स ने दावा किया है कि यह तैयारियां किसी और के लिए नहीं, बल्कि रश्मिका और विजय की शादी के लिए हैं।

वायरल हो रहे एक क्लिप में उदयपुर की एक लग्जरी प्रॉपर्टी में शानदार सजावट और वेन्यू की व्यवस्था दिखाई दे रही है, जिसमें कई यूज़र्स कयास लगा रहे हैं कि दोनों शादी करने वाले हैं। इन विज़ुअल्स ने फैंस के बीच एक्साइटमेंट बढ़ा दिया है, जो लंबे समय से उनके रिश्ते की अफवाहों को फॉलो कर रहे हैं। हालांकि, इन दावों की सच्चाई पर शक बना हुआ है। वीडियो में यह भी दावा किया गया है कि यह 2 फरवरी को होने वाली है।

रश्मिका और विजय अपनी

पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत प्राइवेट रहे हैं। पिछले कुछ सालों में, उन्होंने न तो अपने रिश्ते की पुष्टि की है और न ही सगाई को लेकर चल रही अटकलों पर कोई बात की है। जिस तरह से उन्होंने अपनी प्राइवेसी को बनाए रखा है, उसे देखते हुए ब्लॉगर्स या आस-पास के लोगों द्वारा शादी की तैयारियों जैसी कोई बड़ी डिटेल सामने आने की संभावना कम लगती है। इससे पहले, कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि उनकी शादी 26 फरवरी को उदयपुर में होने वाली है, लेकिन न तो किसी एक्टर और न ही उनकी टीम की तरफ से कोई कन्फर्मेशन आया है। जब तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं आता, वायरल वीडियो वेरिफाइड जानकारी के बजाय अनुमानों पर आधारित लगता है।

रश्मिका, जिन्होंने हाल ही में अपनी आने वाली फिल्म कॉकटेल 2 की शूटिंग पूरी की है, उन्हें शुक्रवार को एयरपोर्ट पर पैपराजी ने छेड़ा भी। जब वह गेट की तरफ जा रही थीं, तो एक फोटोग्राफर ने उन्हें छेड़ते हुए कहा, 'आपने इनवाइट नहीं भेजा।' रश्मिका मुस्कुराईं और जवाब दिया, 'किस चीज़ के लिए?' फिर उन्होंने कैज़ुअली कहा कि उनकी अगली फिल्म की रिलीज में अभी समय है। मज़ेदार पल तब जारी रहा जब पैपराजी ने इशारा किया कि उसे पता है कि वह किस इनविटेशन की बात कर रहा है। रश्मिका अपनी प्रतिक्रिया नहीं रोक पाईं; वह शरमा गईं, हंसीं और जल्दी से आगे बढ़ गईं, जिससे फैंस को इशारों को समझने के लिए छोड़ दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस कपल ने दशहरा के एक दिन बाद 3 अक्टूबर को विजय के हैदराबाद वाले घर पर सगाई की थी। सगाई की सेरेमनी को पूरी तरह से प्राइवेट रखा गया था, और न तो रश्मिका और न ही विजय ने इस मौके पर कोई फोटो जारी की या कोई पब्लिक कमेंट किया।

श्रीकृष्णार्पित गीतायन - अध्याय 7

समग्र बोध योग

माघ मेला, प्रयागराज स्थित कृष्णार्पित पंडाल में सातवें दिवस की कथा

श्रीभगवान उवाच–
ममाध्यक्षेण कौन्तेय,
प्रकृतिः सूयते सचराचरम्।
हेतुनानेन कौन्तेय,
जगद्विपरिवर्तते।।7।।

हे कौन्तेय! मेरी सत्ता और अधिष्ठान में ही यह प्रकृति चर-अचर जगत की उत्पत्ति करती है। मेरे कारण ही यह संसार सृजन, स्थिति और प्रलय के चक्र में प्रवाहित होता है।

कृष्ण कहें–
हे पार्थ! यह जो दिखता जग सारा,
प्रकृति का है यह खेल निराला।
पर आधार मैं स्वयं यहाँ,
बिन मेरे कुछ भी न चलता जहाँ।।
प्रकृति जड़ है, चेतन मैं,
सत्ता, प्रेरक, शासन मैं।
सूरज तपे, चन्द्र शीतल हो,
वायु बहे, जल जीवन हो–
सब मेरी आज्ञा से होता है,
मेरे अधीन विधान यह सोता है।।

माघ मेला प्रयागराज की कथा-परिसर में विवेचन

माघ मेला प्रयागराज के पावन तट पर

कृष्णार्पित ट्रस्ट के दिव्य पंडाल में इंजीनियर देवेंद्र नाथ शुक्ल 'कृष्णार्पित' ने इस गूढ़ तत्त्वज्ञान को अत्यंत सरल और बोधगम्य उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया।

उन्होंने कहा– 'जैसे मशीन अपने-आप नहीं चलती, वैसे ही यह सृष्टि भी स्वतः नहीं चलती। यंत्र को चलाने के लिए संचालक चाहिए, उसी प्रकार प्रकृति के संचालन हेतु परमेश्वर की सत्ता आवश्यक है।'

उन्होंने स्पष्ट किया कि ईश्वर का तत्त्व हस्तक्षेपकारी नहीं, बल्कि साक्षी, नियंता और अधिष्ठाता है। जो मूढ़ नर यह नहीं जान पाते, प्रकृति के खेल में ही उलझ जाते। अहंकार से ढँकी जिनकी दृष्टि, वे माया में खोते अपनी सृष्टि।।

न अवजानन्ति मां मूढाः,
मानुषीं तनुमाश्रितम्।
परं भावमजानन्तो,
मम भूतमहेश्वरम्।।8।।

जो मुझे साधारण मनुष्य मानते हैं, वे मेरे परम भाव को नहीं जानते,
जो समस्त भूतों का ईश्वर है।

इंजीनियर देवेंद्र नाथ शुक्ल जी ने कहा– 'भगवान देहधारी अवश्य प्रतीत होते हैं, किंतु वे देह से बंधे नहीं होते। वे माया में नहीं, अपितु माया उनके अधीन होती है।' यही अज्ञान का मूल है– देह को भगवान मान लेना या भगवान को देह तक सीमित कर देना।

दैवी ह्येषा गुणमयी,
मम माया दुरत्यया।
मामेव ये प्रपद्यन्ते,
मायामेतां तरन्ति ते।।14।।

यह मेरी त्रिगुणात्मिका माया
अत्यंत दुस्तर है।
जो मेरी शरण में आते हैं,
वे ही इस माया को पार कर पाते हैं।

कथा का उपसंहार

माघ मेला के उस कृष्णार्पित पंडाल में यह संदेश बार-बार प्रतिध्वनित हुआ– कर्तापन छोड़ो, शरण लो। प्रकृति से नहीं, प्रकृति के अधिष्ठाता से जुड़ो।

जो मन, बुद्धि और अहंकार को श्रीकृष्ण में अर्पित कर देता है, वही समग्र बोध योग को प्राप्त करता है। ईश्वर-तत्त्व को जान लेने पर जगत का भय मिट जाता है, और जीव माला की मणि नहीं, धागे का साक्षात्कार करने लगता है।

शशि थरूर ने सरकार पर कसा तंज- 'जब मैगजीन में सब छप चुका, तो राहुल को क्यों रोका?'

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। संसद के बजट सत्र के दौरान डोकलाम और चीनी घुसपैठ के मुद्दे पर मचे घमासान के बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सरकार के रवैये पर कड़ा प्रहार किया है। थरूर ने कहा कि राहुल गांधी जो मुद्दा उठा रहे थे, वह पहले से ही सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, ऐसे में सरकार का शोर-शराबा बेवजह था। शशि थरूर ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी 'कारवां' मैगजीन में छपे एक लेख का हवाला दे रहे थे। इस लेख में जनरल नरवणे के उन संस्मरणों का जिक्र है जो अभी प्रकाशित नहीं हुए हैं। थरूर ने तर्क दिया, 'मैगजीन सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है और कोई भी उसे पढ़ सकता है। सरकार को इस बात पर हंगामा करने के बजाय कि किताब छपी है या नहीं, राहुल जी को अपनी बात पूरी करने देनी चाहिए थी।'

सरकार को लोकतांत्रिक मूल्यों की याद दिलाते हुए थरूर ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय का जिक्र किया। उन्होंने कहा, '1962 के चीन युद्ध के दौरान भी संसद में हर दिन बहस होती थी। तब सांसदों पर कोई व्हिप नहीं था और सरकारी सांसद भी खुलकर आलोचना कर पाते थे। 1965 और 1971 के युद्धों में भी देश को भरोसे में लिया गया था, लेकिन आज की सरकार चर्चा से डरती क्यों है?'

थरूर ने स्पष्ट किया कि राहुल गांधी का मकसद सेना पर आरोप लगाना नहीं, बल्कि सरकार के फैसलों पर सवाल उठाना था। उन्होंने कहा, 'अगर सरकार को लगता है कि तथ्य गलत हैं, तो सही तरीका तथ्यों को सुधारना है, न कि सामने वाले को बोलने से रोकना। यह हमारे लोकतंत्र और संसद की गरिमा के लिए अच्छा नहीं है।'

राहुल गांधी ने छेड़ा, सरकार ने रोका, नरवणे की किताब 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' पर क्यों है संग्राम?

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की आत्मकथा 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' प्रकाशक द्वारा 2023 में किए गए पूर्व-आदेश घोषणाओं के अनुसार अप्रैल 2024 में प्रकाशित होनी थी। अमेज़न पर अभी भी इसकी लिस्टिंग है, लेकिन लिखा हैः 'वर्तमान में अनुपलब्ध। हमें नहीं पता कि यह आइटम कब या फिर स्टॉक में वापस आएगा या नहीं। फिर भी, 2026 में यह चर्चा में है क्योंकि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार को लोकसभा में एक पत्रिका की रिपोर्ट पढ़ने की कोशिश की, जिसमें आत्मकथा के कुछ अंश उद्धृत किए गए हैं। जनरल एमएम नरवणे से अक्टूबर में हिमाचल प्रदेश के कसौली में आयोजित एक साहित्य उत्सव में इस विषय पर सवाल पूछा गया था, जहां वे अपनी हाल ही में प्रकाशित उपन्यास 'द कैंटोनमेंट कॉन्स्पिरेसी' पर चर्चा कर रहे थे।

'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' के बारे में उन्होंने कहा था, मुझे लगता है कि यह पुरानी शराब की तरह परिपक्व हो रही है। जितना अधिक समय इसे रखा जाता है, यह उतनी ही पुरानी और मूल्यवान होती जाती है। उन्होंने कथित तौर पर महोत्सव में एक अतिथि से कहा, 'मेरा काम किताब लिखना और उसे प्रकाशकों को देना था। प्रकाशकों को रक्षा मंत्रालय से अनुमति लेनी थी। उन्होंने आगे कहा, यह अभी भी एक साल से अधिक समय से समीक्षाधीन है।

उन्होंने आगे कहा कि लेकिन मुझे किताब लिखने में आनंद आया, चाहे अच्छा हो या बुरा। बस यही बात है। रक्षा मंत्रालय जब चाहे तब अनुमति दे सकता है। पूर्व वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों द्वारा लिखी गई पुस्तकों की संवेदनशील सामग्री की जाँच के लिए समीक्षा करना एक सामान्य प्रक्रिया मानी जाती है, लेकिन जनरल नरवणे की पुस्तक विवादों में घिर गई क्योंकि इसमें अग्निपथ योजना और गलवान संघर्ष जैसे मुद्दों पर चर्चा का खुलासा हुआ था, जिसमें चीनी सैनिकों के साथ झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। जनरल एमएम नरवणे ने दिसंबर 2019 से अप्रैल 2022 तक भारत के सेना प्रमुख के रूप में कार्य किया।

जब राहुल गांधी ने 'द कारवां' पत्रिका में प्रकाशित एक रिपोर्ट पर बोलने का प्रयास किया, जिसमें कथित तौर पर गलवान और 'चीनी पक्ष से टैंकों के आने' के बारे में उनके संस्मरण के कुछ अंश उद्धृत किए गए थे, तो रक्षा और गृह मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह ने आपत्ति जताई।

अशोकनगर कॉल सेंटर को सिंधिया ने घोषित किया जिले का नया 'नवरत्न'

अशोकनगर। केन्द्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री तथा गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज अशोकनगर कलेक्ट्रेट में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (अर्घ्र्ं) की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के बाद आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने अशोकनगर के सर्वांगीण विकास के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। केन्द्रीय मंत्री ने अशोकनगर के लिए रोजगार, सिंचाई और इन्फ्रास्ट्रक्चर सहित कई क्षेत्रों में चल रही परियोजनाओं की जानकारी दी। इस बैठक में जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधि एवं पार्टी पदाधिकारी उपस्थित रहे।

'दिशा' बैठक में तय हुई अशोकनगर के विकास कार्यों की स्पष्ट समय-सीमा

अशोकनगर की गहन दिशा बैठक के दौरान केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिले के समग्र विकास, प्रशासनिक कार्यप्रणाली और जनसेवा की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, पेयजल, अधोसंरचना, रोजगार, उद्योग और नगरीय विकास से जुड़ी योजनाओं की वस्तुस्थिति पर चर्चा हुई तथा विभिन्न विभागों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए। केन्द्रीय मंत्री ने निम्नलिखित परियोजनाओं के बारे में जानकारी दीः 100 बिस्तर वाले अस्पताल में रिक्त पदों में से 40 पद (पीडियाट्रिशियन, मेडिकल ऑफिसर, नर्सिंग स्टाफ) भर दिए गए हैं। साथ ही, 300 बिस्तर वाले नए अस्पताल को मई 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है, जिसके लिए अग्रिम स्टाफ स्वीकृति के निर्देश दिए गए हैं।

550 करोड़ की 'चंदेरी माइक्रो इरिगेशन परियोजना' को जून 2026 तक पूर्ण करने की समय-सीमा तय की गई है। वहीं, ?1,572 करोड़ की 'राजघाट वाटर सप्लाई स्कीम', जिससे 812 गाँवों को लाभ मिलेगा, को दिसंबर 2026 तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

अशोकनगर कॉल सेंटर को जिले का नया 'नवरत्न' बताते हुए सिंधिया ने कहा कि वर्तमान में यहाँ 505 युवाओं को सीधा रोजगार मिल रहा है। इसके विस्तार हेतु मारुति शोरूम के पास 1000 सीटों की क्षमता वाली नई इमारत निजी क्षेत्र के सहयोग से बनाई जाएगी। साथ ही, ट्रांसपोर्ट नगर के विस्थापन के लिए भी समय-सीमा तय करने के निर्देश कलेक्टर को दिए गए हैं।

इंफ्रास्ट्रक्चर और सौंदर्यीकरण पर दिया गया खास ध्यान

केन्द्रीय मंत्री ने प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि भाजपा सरकार अशोकनगर के सौंदर्यीकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास ध्यान दे रही है। इस बैठक में इन मुद्दों पर बड़े निर्णय लिए गए हैं। सिंधिया ने बताया कि शहर में ?45 करोड़ की लागत से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण तीन चरणों में किया जाएगा। साथ ही तुलसी सरोवर एवं थीम रोड सहित शहर सौंदर्यीकरण के लिए 40 करोड़ की योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि शाडोरा से करीला माता मार्ग (55 किमी) को दिसंबर 2026 तक पूर्ण किया जाएगा, जबकि पुरवाई-मुंगावली-चंदेरी मार्ग (81 किमी) को जून 2026 तक जनता को समर्पित किया जाएगा।

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन एवं प्रदेश मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नेतृत्व में जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से जिले के सर्वांगीण और समावेशी विकास को गति दी जा रही है।

पाकिस्तान में आतंकवाद रोधी कोर्ट का सख्त फैसला

इमरान खान की बहन के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी

इस्लामाबाद **(एजेंसी)**। पाकिस्तान की रावलपिंडी स्थित आतंकवाद-रोधी अदालत (एटीसी) ने नवंबर 2024 में हुए विरोध प्रदर्शन के मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन अलीमा खान के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। स्थानीय मीडिया के अनुसार, अदालत ने यह वारंट सुनवाई में लगातार अनुपस्थिति और बार-बार समन के बावजूद पेश न होने के कारण जारी किया। सुनवाई के दौरान अलीमा खान के वकील फैसल मलिक ने दलील दी कि जब तक उनके मुवक्किल के बैंक खाते और पहचान पत्र फ्रीज हैं, तब तक वे अदालत में पेश नहीं होंगी। इस पर विशेष अभियोजक ज़हीर शाह ने कहा कि कोई भी आरोपी अदालत को शर्तें नहीं बता सकता या कार्यवाही में बाधा नहीं डाल सकता। उन्होंने अलीमा खान के व्यवहार को शुरू से ही गैर-जिम्मेदाराना बताया।

अदालत ने अलीमा खान की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की मांग खारिज करते हुए उनके ज़मानती को नोटिस जारी किया और सुनवाई 3 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी। अदालत ने रावलपिंडी के पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया कि अलीमा खान को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जाए। साथ ही कहा कि उनके बैंक खाते और पहचान पत्र तब तक फ्रीज रहेंगे, जब तक वे अदालत में पेश नहीं होतीं। यह मामला 26 नवंबर 2024 के विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है, जिसमें अलीमा खान सहित 10 अन्य आरोपियों पर मामला दर्ज है। उस दिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के समर्थकों ने सार्वजनिक सभाओं पर लगे प्रतिबंध को तोड़ते हुए इस्लामाबाद में प्रवेश किया और डी-चौक के पास कानून-व्यवस्था बलों से झड़प हुई। हालात काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया था। इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर पीटीआई का तीन दिवसीय प्रदर्शन हिंसा के बाद अचानक समाप्त हो गया।

इसी बीच, पीटीआई ने कराची और सिंध के अन्य हिस्सों में पार्टी कार्यकर्ताओं की कथित हिरासत के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट का रुख किया है। पार्टी का आरोप है कि मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस के तहत की गई छापेमारी में 180 से अधिक कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया।

बलूचिस्तान में 'ऑपरेशन हेरोफ' का कहर

बीएलए ने जारी की दो महिला हमलावरों की फोटो आईएसआई हेडक्वार्टर को बनाया था निशाना!

पेशावर **(एजेंसी)**। पाकिस्तान का सबसे बड़ा और अशांत प्रांत बलूचिस्तान एक बार फिर दहल उठा है। प्रतिबंधित संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने 'ऑपरेशन हेरोफ' (ब्लैक स्टॉर्म) के दूसरे चरण के तहत पूरे प्रांत में समन्वित हमले किए हैं। इन हमलों में अब तक 17 सुरक्षाकर्मियों सहित लगभग 50 लोगों की जान जा चुकी है। इस बार के हमलों ने दुनिया का ध्यान इसलिए खींचा क्योंकि इसमें महिला फिदायीन (आत्मघाती हमलावरों) का इस्तेमाल किया गया है। वहीं बीएलए ने दो महिला हमलावरों की तस्वीरें जारी की हैं जिनमें से एक की पहचान 24 वर्षीय आसिफा मेंगल के रूप में हुई है।

बीएलए ने दो महिला हमलावरों की तस्वीरें जारी की हैं जिनमें से एक की पहचान 24 वर्षीय आसिफा मेंगल के रूप में हुई है। नुश्की की रहने वाली आसिफा ने अपने 21वें जन्मदिन पर बीएलए की मजीद ब्रिगेड जॉइन की थी।जनवरी 2024 में उसने फिदायीन बनने का फैसला किया और शनिवार को नुश्की स्थित पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के मुख्यालय को निशाना बनाया। एक वीडियो संदेश में उसने बलूच नागरिकों से एकजुट होने और पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाने की अपील की है।

पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और उग्रवादियों के बीच पिछले 40 घंटों से खूनी जंग जारी है। पाकिस्तान के कनिष्ठ मंत्री तलाल चौधरी के अनुसार, हमलावर नागरिक वेशभूषा में स्कूलों, बैंकों और अस्पतालों में घुस गए और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। नुश्की, हब, चमन, नसीराबाद, ग्वादर और मकरान जैसे क्षेत्रों में एक साथ हमले किए गए। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुगती ने बताया कि अब तक 140 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया गया है। सेना का दावा है कि उग्रवादियों के किसी भी शहर या रणनीतिक ठिकाने पर कब्जे की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। बलूचिस्तान क्षेत्रफल के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन आर्थिक रूप से सबसे पिछड़ा प्रांत है। यहां गैस और खनिजों का भंडार है लेकिन बलूच समूहों का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार और विदेशी कंपनियां (खासकर चीन) उनका शोषण कर रही हैं। बीएलए जैसे अलगाववादी समूह दशकों से पूर्ण स्वतंत्रता और संसाधनों में बड़े हिस्से की मांग को लेकर सशस्त्र विद्रोह कर रहे हैं।

ज़ेलेंस्की का ऐलान : रूस-यूक्रेन शांति वार्ता अगले सप्ताह अबू धाबी में

डोनबास और कब्ज़े वाले भू-भाग पर मतभेद जारी

कीव **(एजेंसी)**। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने रविवार को घोषणा की कि रूस और यूक्रेन के बीच अगली शांति वार्ता 4 और 5 फ़रवरी को अबू धाबी में होगी। वार्ता में रूस, यूक्रेन और अमेरिका के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। ज़ेलेंस्की ने अपने टेलीग्राम पोस्ट में कहा'हमारी वार्ता टीम से रिपोर्ट मिली है। अगली तीनतरफा बैठक के लिए तारीखें तय हो गई हैं। यूक्रेन सार्थक वार्ता के लिए तैयार है और हम चाहते हैं कि यह युद्ध के वास्तविक और गरिमापूर्ण अंत की दिशा में ले जाए।' हालाँकि, अमेरिकी और रूसी अधिकारियों की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। रूस और यूक्रेन की सरकारें अभी भी कई अहम मुद्दों पर सहमति नहीं बना पाई हैं। सबसे बड़ा विवाद डोनबास क्षेत्र में रूसी कब्ज़ा और अन्य क्षेत्रों के भविष्य को लेकर है। इसी बीच, रूसी हमले भी लगातार जारी हैं। रविवार सुबह, दक्षिणी यूक्रेन के ज़ापोरिज़्ज़िया शहर में रूसी ड्रोन ने एक मातृत्व अस्पताल पर हमला किया। यूक्रेनी आपातकालीन सेवा ने टेलीग्राम पोस्ट में बताया कि हमले में तीन महिलाएं घायल हुईं और गाइनेकोलॉजी वार्ड में आग लगी, जिसे बाद में बुझाया गया। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि रूस ने अस्थायी रूप से कीव और अन्य शहरों पर हमले रोकने पर सहमति दी है, ताकि ठंडे मौसम में नागरिकों की हालत बिगड़े। क्रेमलिन ने शुक्रवार को कीव पर हमले रोकने की पुष्टि की, लेकिन कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी। पिछले सप्ताह रूस ने दक्षिणी यूक्रेन के ओडेसा, उत्तर-पूर्वी खार्किव और कीव क्षेत्र में भी हमले किए।

रिवोल्यूशनरी गार्ड मुद्दा : ईयू के फैसले से भड़का ईरान, यूरोपीय संघ के सभी राजदूतों को किया तलब

तेहरान **(एजेंसी)**। ईरान ने यूरोपीय संघ के उस फैसले के विरोध में अपने सभी ईयू राजदूतों को तलब किया है, जिसमें ईरान की अर्द्धसैनिक इकाई रिवोल्यूशनरी गार्ड को आतंकी संगठन घोषित किया गया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघाई ने पत्रकारों को बताया कि इन राजदूतों को रविवार को तलब किया गया था। ईरान ने इस कदम को राजनीतिक दबाव और अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप करार दिया है। इसके साथ ही ईरानी अधिकारियों ने कहा है कि वे ईयू के फैसले को 'गैरकानूनी' और 'अस्वीकार्य' मानते हैं और आवश्यक कूटनीतिक कार्रवाई करने का संकेत दिया है।

यूरोपीय संघ ने जनवरी में ईरान में हुए विरोध प्रदर्शनों पर रिवोल्यूशनरी गार्ड की कथित हिंसक कार्रवाई और दमन के आधार पर इसे आतंकवादी समूह घोषित किया था। ईयू के इस निर्णय के बाद से ईरान-यूरोप संबंधों में तनाव बढ़ा है, और ईरान ने कई बार पश्चिमी देशों पर दखलअंदाजी का आरोप लगाया है। राजदूतों को तलब करने का यह कदम ईरान की कूटनीतिक प्रतिक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है, जिससे यूरोपीय संघ के साथ संवाद और सहयोग के स्तर पर बदलाव की संभावना बढ़ गई है।

यूक्रेन में रूसी सुसाइड ड्रोन का हमला : बस में जिंदा जल गए दर्जनों लोग, हर तरफ बिछ गई लाशें

कीव **(एजेंसी)**। यूक्रेन के पाल्लोहराद जिले में शनिवार को रूस ने एक गंभीर ड्रोन हमला किया। रूसी सुसाइड ड्रोन ने खदानों में काम करने वाले मजदूरों को ले जा रही एक सर्विस बस को निशाना बनाया। हमले के बाद बस में भीषण आग लग गई और वह जलकर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इस हमले में कम से कम 15 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।

यह हमला डीटीईके कोल कंपनी के पास हुआ। कंपनी के सीईओ मैक्सिम टिमचेंको ने इसे निहत्थे नागरिकों पर किया गया आतंकवादी हमला बताया। उन्होंने कहा कि यह डीटीईके कर्मचारियों के लिए अब तक की सबसे बड़ी त्रासदी है और कंपनी के इतिहास का सबसे काला दिन है। उन्होंने मृतकों और घायलों के परिवारों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने इस घटना पर गहरा दुख जताया। उन्होंने बताया कि पाल्लोहराद जिले के टर्निव्का इलाके में एक आम बस को रूसी ड्रोन ने निशाना बनाया। जेलेंस्की ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इस हमले के बावजूद यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध समाप्त करने के लिए कूटनीतिक प्रयास जारी हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जानकारी दी कि अमेरिका की मध्यस्थता में 4 और 5 फरवरी को अबू धाबी में त्रिपक्षीय बैठक होगी। यूक्रेन ने इस बैठक में सार्थक बातचीत के लिए तैयार रहने की बात कही है। यह घटना एक बार फिर दिखाती है कि रूस-यूक्रेन युद्ध में आम नागरिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। राहत और बचाव कार्य जारी हैं और प्रभावित परिवारों की मदद की जा रही है।

Facebook: https://www.facebook.com/profile.phpid=100063787346044 **Twitter:** https://twitter.com/mantrabharatt=8tJONQ7H-h6EKqqap2tVMw&s=08 **Mobile No:** 7007837917

मंत्र भारत : R.N.I. MAHHIN/ 2016/65841 स्वात्वाधिकारी राकेश शर्मा के लिए राकेश शर्मा द्वारा AIS Printing solution प्लॉट नं0-A- 544 TTC इंडस्ट्रियल एरिया एमआईडीसी माहपे-नवी मुंबई, थाने 400709 से मुद्रित एवं शाप.नं. 36, द्वितीय तल, प्लाट -490.1. जाम मील बिल्डिंग, डॉ बाबा साहेब अम्बेकर रोड, लाल बाग परेल, मुम्बई-400012प्रकाशित एवं सम्पादित । कार्यालय : शाप.नं. 36, द्वितीय तल, प्लाट -490.1. जाम मील बिल्डिंग, डॉ बाबा साहेब अम्बेकर रोड, लाल बाग परेल, मुम्बई-400012 । फोन : 022-24706563 । कार्यकारी सम्पादक- योगेन्द्र चौधरी
E-Mail : editormantrabharat@gmail.com mantrabharatmumbai@gmail.com । सम्पादक : विनोद आर शर्मा, मोबाइल : 7007837917 । समूह सम्पादक : डॉ दयानन्द तिवारी। वैधानिक सूचना : मंत्र भारत से संबंधित समस्त विवाद निपटारे के लिए मंत्र प्रधान कार्यालय क्षेत्र प्रयागराज/इलाहाबाद न्यायालय ही होगा। प्रधान कार्यालयः 80ए मेंहदौरी, तेलियरगंज, प्रयागराज-211004 (नोटः कानूनी पत्र व्यवहार का पता प्रधान कार्यालय ही होगा।)